

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜ਼ੌਂ° 25] No. 25]

नर्द बिल्ली, शनिबार, जून 24, 1978/आषाढ़ 3, 1900

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1978/ASADHA 3, 1900

इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

माग II—व्यव्य 3—उप-व्यव्य (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केम्ब्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सोविधिक ग्रावेश और ग्रधिसुचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत भिवचिन ग्रायोग

नई विल्ली, 2 जून, 1978

भां० आ(० 1783 — नोक प्रतिनिधित्व प्रधितियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 43क की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त गिक्सियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन प्रायोग, मिक्किम सरकार के परामर्थ से, श्री डी० के० मानवलन के प्रवकाग के दौरान श्री घार० के० गुप्ता, सिच्च, विधान सभा, तथा घपर मिच्च (गृह) को निवियम राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन घाफिसर के लग में एतद्द्वारा नाम निर्वेशित करना है।

[स० 154/मिखिकम/78]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 2nd June, 1978

S.O. 1783—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim, hereby nominates Shri R. K. Gupta, Secretary, Legislative Assembly and Additional Secretary (Home) as the Chief Electoral Officer for the State of Sikkim during the absence on leave of Shri D. K. Manavalan

[No 154/SKM/78]

भावेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

का० आ० 1784. — यत, निर्वाचन भ्रायोग का समाधान हो गया

ा मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्धाचन के लिए 105—थिस्थाला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदबार श्री के० करुणाकरण पिल्लई, बालूपारमबिल, पाल्य ग,
थिसवाल्ला, जिला भ्रत्लेप्पी (केरल राज्य) लोक प्रतिलिनित्य आ ान्ते,
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो हारा अपेक्षित के भन्वर
लया रीति से श्रपने निवचिन व्ययों का लेखा दाखिल का प्रसफल रहे है,

श्रौर, यत. उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, श्रपनी इस श्रसफलता के लिए कोई कारण श्रयवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, श्रौर, निर्वाचन श्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस श्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

श्रत , श्रव उक्त श्रिधिनियम की धारा 10-क के श्रनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एतत् श्रारा उक्त श्री के० करणाकरन पिल्लई को संसद के किसी भी सबन के या किसी राज्य की विधान-सभा श्रथका विधान परिषद् के सबस्य चुने जाने श्रीर होने के लिए इस श्रावेण की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निर्रोहत घोषित करता है।

त्रावेश से.

[स॰ केरल-वि० सं०/105/77]

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1978

S.O. 1784.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. Karunakaran Pillai, Valuparambil, Paliakkara, Thiruvalla, Alleppey District (Kerala State), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 105-1 huuvalla constituency, has falled to lodge the account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declates the said Shri K. Karunakaran Pillai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/105/77]

स्रादेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1978

कां आं 1785.— यत, निर्वाचन ग्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए गाधारण निर्वाचन के लिए 122 चयारा निर्वाचन-केल से चुनाय लड़ने वाले उम्मीदतार थी वरगीस जोर्ज, एडवोकेट, क्वीसोन (बेरल राज्य) लोक प्रतिनिधित्व प्रिधिनयम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रपेक्षित प्रपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे प्रसक्त रहे है.

श्रीर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, भ्रपनी इस श्रमफलता के लिए कोई कारण ग्रथवा स्पष्टीकरण नहीं विया है, निव चिन ग्रायोग का यह भी समाधान हो गया कि उसके पास इस ग्रसफलत के लिए कोई पर्याप्त कारण या र पोचिस्य नहीं है,

श्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के श्रनुसरण में निर्वाचन श्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री वरगीम जोर्ज को ससद के किसी भी सदन के या किसो राज्य की विश्वाद सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के लिए निर्रेहिन घोषित करता है।

> [मं० केरल-वि०स०/122¹77] वी० नागमुख्रद्वाण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th May, 1978

S.O. 1785.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Varghese George, a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in March, 1977 from 122-Chavara constituency, has failed to lodge the account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate even after due notices, has not given any reason of explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said

Shri Verghese George, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/122/77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

नई दिल्ली, 8 जून, 1978

कां आ 1786 — लोक प्रतिनिधित्व ग्रिधिनियम, 1953 की धारा 106 के ग्रनुसरण में, निर्वाचन ग्रामोग, 1977 की निर्वाचन ग्रर्जी सं 01 मे जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के तारीख 15 मई, 1978 का निर्णय एतद द्वारा प्रकाणित करता है।

> ग्रार० डी० धर्मा, श्रवर सचिव [सं० 82/राज०लो०सं०/1/77]

S. B. Election Petition No. 1 of 1977, Kishan Lal Shah Vs. Nithuram Mirdha and another.

15th May, 1978

Hon'ble Sharma J.

15-5-78 Hon'ble Sharma J.

Mr. B. R Arora-for the petitioner.

Mr. M. M. Singhvi-for non-petitioner No. 1,

Mr. B. K Mohanani-for non-petitioner No. 2.

Shri Kishan Lal Shah, Election petitioner, applied for withdraw of his election-petition by way of which he questioned the election of Shri Nathu Ram Mirdha to the Lok Sabha from Nagpur Parliamentary Constituency (No. 25). The withdrawal was sought on the ground that the petitioner is not keeping good health and is unable to pursue the election petition. A date for the hearing of this application was naed and a notice thereof was given to the non-petitioners and published in the Rajasthan, Raj Palra inc. Official Gazette on 12-2-1978. The non-petitioners No. 1 and 2 raised no objection to the application for withdrawal. They, however, pleaded that in case the application for withdrawal was allowed, the petitioner might be ordered to pay the costs of the non-petitioners heretobefore incurred.

Arguments on the application for withdrawal were heard on 20-2-78 and the application of the petitioner for withdrawal of the election petition was granted as in the opinion of this Court there were just and reasonable grounds for withdrawal thereof and the application had not been induced by any bargain or consideration. The petitioner was ordered to pay Rs 500, as costs to Mr. M. M. Singhvi, learned counsel for the non-petitioner No. 1 and Rs. 250, to Mr. B. K. Mohanani, learned counsel for non-petitioner No. 2, out of the security amount deposited. A notice of the withdrawal was published in the Rajasthan Raj Patra, i.e. official gazette as well as in daily Hindi newspaper "Rajasthan Patrika', which has wide circulation in Rajasthan, on 27-4-1978. After publication of the notice of withdrawal, no person has applied within 14 days of such publication to be substituted in place of the party withdrawing, i.e. Kishan I al Shah.

Hence, the election-petition filed by Kishan Lal Shah against the non-petitioners Nos. 1 and 2, namely, Nathu Ram Mirdha and Radha Kishan, is dismissed as withdrawn and a report of this fact be sent to the Election Commission of India immediately under section 111 of the Representation of the People Act.

Sd/-Hon'ble. Sharma J.

विस महालय

(राजस्य विभाग)

नई विल्ली, 20 श्रप्रैल, 1978

आय-कर

कार्य आर्थ 1787 --केन्द्रीय गरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुए, "वीरायतन, नालन्दा" की निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए ग्रीर में उक्त धारा के प्रयोजनार्थ ग्रिधिसूचित करती है।

[स॰ 2277 (फा॰ स॰ 197/184/77—स्वा॰ क॰ (ए) 1]

MINISTR YOF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th April, 1978

(Income-Tax)

S.O. 1787.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Veerayatan, Nalanda" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1975-76.

[No. 2277 (F. No. 197/184/77-II(AI)]

नई दिल्ली, 27 प्रश्रीत, 1978

(भ्राय-कर)

का० आ० 1788.—केन्द्रीय सरकार, ग्राय-कर ग्रिधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री ऋल्वालगर मन्दिर, श्रलगर कोयल, मेसूर तालुक, जिला मदुरई, तामिल नाड्" को उक्त धारा के प्रयोजनो के लिए तामिल नाड़ राज्य में सर्वव विख्यात लोक पूजा का स्थान **श्रिधसुचित** करती है ।

[सं॰ 2285(फा॰ सं॰ 176/38/78-म्रा॰क॰ (ए1)]

New Delhi, the 27th April, 1978

(Income-Tax)

S.O. 1788.—In exercise of the powers conferred by subsection (2)(b) of section 80(G) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Covernment hereby notifies "Shri Kallalagar Temple, Alagar Koil, Melur, Taluk Madural District, Tanul Nadu", to be a place of public worship of renown throughout the State of Tanul Nadu for the proposes of the said Section.

[No. 2285 (F. No. 176/38/78-II(A1)]

(म्राप-कर)

का० अ० 1789 -- केन्द्रीय सरफार, श्राय-कर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपप्रारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त णक्तियो का प्रयोग करते हुए "ग्ररुल मिधू जिन्तामणिनाथ स्त्रामी मन्दिर" की निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए प्रौर से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ भिधमुचित करनी है।

> [শিও 2286 (দাতি শৃও।/97/69/77 স্থাতি কাও(দু)]] एम० शास्त्री, प्रवर सचिव

(Income-Tax)

S.O. 1789.— In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu Chinthamoninathaswami Temple, Vasudevanallur" for the purpose of the said section for and from the assessment year(\hat{s}) 1975-76.

> [No. 2286 (F. No. 197/169/77-II(AJ)] M. SHASTRI, Under Secy.

सई विल्ली, ६ जून, 1978

का० आ० 1790.---राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) की शसी के धन सार, केन्द्रीय गरकार एतद्वारा, प्राधिस्चित करती है कि प्रतस्ची मे उस्लिखित प्रायकर विभाग के अधिकार क्षेत्रो/ कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

प्रनुसूची

- आयकर आयक्त, अगगण का अधिकार क्षेत्र।
- ३ ग्रायकर ग्रायुक्त, इलाहाबाद का ग्राधिक। भेता।
- आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश-I श्रीर मध्य प्रदेश-II का भ्रधिकार
- 4 ग्रायकर ग्राय्क्त, दिल्ली का ग्राधिकार क्षेत्र।
- 5 अविकर आयुक्त, राजस्थान, जयपूर तथा जोधपुर का अधिकार क्षेत्र।
- अायकर भायक्त, लखनऊ का भ्रधिकार क्षेत्र।
- ग्रायकर भ्रायुक्त, कानपुर का प्रधिकार क्षेत्र।
- श्रायकर श्रायक्त, मेरठ का श्रधिकार क्षेत्र ।
- श्रायकर श्रायक्त, नागपूर का श्रधिकार क्षेत्र।
- ग्रायकर प्रायक्त, बिहार-I ग्रीर बिहार-II का ग्रधिकार क्षेत्र।
- ग्रायकर ग्रायुक्त, हरियाणा तथा चडीगढ़, रोष्टतक का भ्रधिकार क्षेत्र।
- 12. प्रायकर प्रायक्त गजरात के प्रधिकार क्षेत्र।
- ।३ श्रायकर भायक्त, पूर्ण के श्राधिकार क्षेत्र।
- श्रायकर श्रायक्त, पटियाला का अधिकार क्षेत्र।
- 15 प्रायक्षर धाय्क्त, प्रमृतसर का प्रधिकार क्षेत्र।
- 16 निरीक्षण निवेशालय (भायकर), नई दिल्ली।
- 17 निरीक्षण निदेशालय (जांच), नई दिल्ली।
- 18 निरीक्षण निदेश।लय (ग०स० प्र०) , नई दिल्ली ।
- गंगठन तथा प्रबन्न (श्रायकर) सेवा निदेणालय, नई दिल्ली।।
- 20. भारतीय राजस्व सेवा प्रत्यक्ष कर कर्मभारी महाविद्यालय, नागपुर।

फा॰ स॰ ई॰-11017/60/78-प्रणा॰ ix] रमा कान्त, अवर सचिय

New Delhi, the 6th June, 1978

6.0. 1790.—In terms of Rule 10(4) of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify that the employees of the Charges/Offices of the Income-tax Department, specified in Charges/Offices of the Income-tax Department, specified in Charges/Offices of Hindi the Schedule, have acquired a working knowledge of Hindi.

SCHEDULE

- 1. Charge of the Commissioner of Income-tax, Agra.
- 2. Charge of the Commissioner of Income-tax, Allahabad.
- 3. Charges of the Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh-I and Madhya Pradesh-II.
- 4. Charges of the Commissioners of Income-tax, Delhi.
- 5. Charges of the Commissioners of Income-tax, Rajasthan, Lipur and Jodhpur.
- 6 Charge of the Commissioner of Income-tax, Lucknow.
- 7. Charge of the Commissioner of Income-tax, Kanpur.

- 8. Charge of the Commissioner of Income-tax, Mecrut.
- 9. Charge of the Commissioner of Income-tax, Nagpur
- Charges of the Commissioner of Income-tax, Bihar-I and Bihar-II.
- Charge of the Commissioner of Income-lax, Haryana & Chandigarh, Rohtak.
- 12. Charges of the Commissioners of Uncome-tax, Gujarat.
- 13. Charge of the Commissioner of Income-tax, Pune.
- 14. Charge of the Commissioner of Income-tax, Patiala.
- Charge of the Commissioner of Income-tax, Amitsar.
- 16. Directorate of Inspection (I.T.), New Delhi.
- 17. Directorate of Inspection (Inv.), New Delhi.
- 18. Directorate of Inspection (Research, Statistics & Publication), New Delhi.
- Directorate of Organisation & Management Services (Income Tax), New Delhi.
- Directorate of Training, Indian Revolue Service (Direct Taxes), Staff College, Nagpur.

[F. No. E-11017/60/78-Ad, IX] RAMA KANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

(ब्राय-कर)

कां आ 1791:—-प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के प्रनुसरण में श्रीर राजस्य विभाग में भारत सरकार की प्रधिसूचना सं 1911 (फार सं 404/27/77-प्राई० टी० सी० सी०), दिनांक 29-7-1977 तथा सं 1206 (फार सं 404/4/76-प्राई० टी० सी०, दिनांक 17-1-1976 के प्रतिलंघन में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री भार० वी० पी० सिन्हा भीर श्री पी० कच्छप को, जो केन्द्रीय सरकार के राज-पत्रित प्रधिकारी हैं, उक्त प्रधिनियम के भन्तर्गत कर-बसूली ग्रधिकारी की प्रविनयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह प्रश्चिमूचना श्री भार० बी० पी० सिम्हा तथा श्री पी० कच्छप के कर बसूली ग्रधिकारी के रूप में कार्य-भार संभालने की तारीख से लागृ होगी।

[मं० 2299(फा०सं० 404/27/77-ब्राई०टी०सी०सी०)]

एक० बेकटरामन्, उप सन्तिव

New Delhi, the 15th May, 1978 (Income-Tax)

- 8.0. 1791.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue No. 1911 (F. No. 404/27/77-ITCC) dated 29-7-77 and No. 1206 (F. No. 404/4/76-ITCC) dated 17-1-1976 the Central Government hereby authorises Sharvshri R. V. P. Sinha and P. Kachhap being a Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Sarvshri R. V. P. Sinha and P. Kachhap take over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 2299 (F. No. 404/27/77-ITCC)]
H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विकाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

(नई दिल्ली, 12 जून, 1978

कार कार 1792.—राष्ट्रीयकृत बैक (प्रबन्ध मीर प्रकीण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री एम व्यव्याणि के स्थान पर वित्त मंत्रालय, श्राधिक कार्ये विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री एन व्यार रंगनाथन की एतद्वारा इंडियन बैंक के निवेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/16/78 बी० घो०-1(1)] च० थ० मीरचन्दानी, ग्रवर सचिष

(Department of Economic Affairs) (Banking Division)

New Delhi, the 12th June, 1978

S.O. 1792.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri N. R. Ranganathan, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Indian Bank vice Shri M. Dandapani.

[No. F. 9/16/78-BO. I(1)] C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

वाणिज्य नागरिक पृति तथा सहकारिता मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, भायात-निर्यात का कार्यालय)

भ्रावेश

नई विल्ली, 1 जून, 1978

कां आ । 1792.—सर्वंशी हिम्बुस्तान इस्पात लिं , भिलाई इस्पात योजना, भिलाई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग (भ॰ प्र॰) को 53,56,000 रु० (तिरेपन लाख, छप्पन हजार रुपए माझ) का एक झायात लाइसेंस सं॰ आई/डी॰ 1077989/टी॰ /सी/मार/एच/65/77 दिनोक 15-11-77 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की श्रनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस झाधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस झाधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा यह बताया गया है कि मूल विनियम नियंत्रण प्रति सीमा-सुरूक प्राधिकारियों के पास पजीकृत नहीं करवाई गई थी। उसका उपयोग कर लिया गया है।

- 2. इस तर्क के समर्थन में माबंदक ने गण्य—मायुक्त के प्रमाण-मब्र के माथ एक गण्य-पन्न दाखिल किया है। मै, तदनुमार, संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है। इसलिए यथा सगोधित प्रायात (नियंत्रण) श्रादेग, 1955 दिनांक 7-12-55 की उप-वारा 9(सी सी) के भन्तर्गंत प्रवक्त मधिकारों का उपयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान इस्पात लि०, (बी एस\पी) के नाम में जारी किए गए लाइसेस स० श्राई/डी/1077989/टी/सी श्रार/एच/65/77 दिनांक 15-11-77 को एसव्द्रारा रह किया जाता है।
- 3. लाइसेसधारी को उक्त लाइसेन की अनुलिप मुद्रा विनिभय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[म॰ एच एम एल/बी-13/77-78/वी एल एस (ए)] ए० एल० भल्ला, उप-मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Office of the Dy. Cldef Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 1st June, 1978

- S.O. 1793.—M/s. Hindustan Steel Ltd., Bhila; Steel Plant, Bhilai Dist. Durg. (M.P.) were granted an import licence No. I|D|1077989|T|CR|H|65|77 dated 15-11-77 for Rs. 53,56.000 (Rupees fifty three lakhs and fifty six thousand only). They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original Exchange Purposes copy was not registered with the Customs authorities It has not been utilised.
- 2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit along with a certificate from Oath Commissioner. I am accordingly satisfied that the original exchange Control Purpose copy of the said licence has been lost. Therefore in exercise of the powers conferred under Sub-clause 9(cc) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-55 as amended the said original Fxchange Control purposes copy of licence No. I|D|1077989|T|CR|H|65|77 dated 15-11-77 issued to M/s. Hindustan Steel L'd. (BSP), is hereby cancelled.
- 3. A duplicate Exchange Control purposes copy of the said licence is being issued separately to the Licensee.

[No. HSL/B-13/77-78/PLS(A)]
A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

(विवेश क्यापार विभाग)

(उप मुख्य नियंत्रक, भावात-निर्यात का कार्यालव)

जादेश

ब्रह्मदाबाद, 5 जूम, 1978

का॰ आ० 1794 — सर्वश्री कुल बिहारी रौलर फ्लोर मिस्स, पोस्ट बाक्स नं० 7, गोधरा-बड़ीया हाईवे, गोधरा को सिस्क/नाइलन/पोलिएस्टर बोलटिंग कपड़ा और ग्रिट गांज स्टीस प्लेटिङ कायर कपड़ा चिल्ड कास्ट झायरन रोशसं के लिए 20,000 क्पन्ने (बीस हजार रुपए मान्न) के लिए झायात लाइसेंस सं० बी०/ए/1877837, विमाक 20-11-1977 प्रदान किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेंग को 20,000 स्पण के लिए सीमा-शुक्क प्रयोजभ प्रति एवं मुद्रा विनिध्य निवसण प्रति की अमुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुक्क प्रयोजन प्रति चौर मुद्रा विनिध्य निवंत्रण प्रति किसी भी पक्तन प्राधिकारी से पंजीकृत कराए विना घीर विस्कुल उपयोग में लाए विभा ही खोई गई/ ग्रस्थानस्थ हो गई है ।

घपने तर्क के समर्थन में ग्राबेदक ने एक शपथ-पश्च वाखिल किया है।

मैं सन्तुष्ट हु कि लाइसेस स० पी०/ए/1877837, दिलांक 3-11-1977 की सीमा नृत्क प्रौर मुद्रा विनिभय नियत्रण प्रति खो गई है भीर निदेश वेता हूं कि श्रावेदक की उक्त लाइसेस की सीमा शुरूक प्रयोजन प्रति भीर मुद्रा विनिभय नियंत्रण प्रति की धनिलिपि प्रति जारी की जामी चाहिए।

लाइसेंग स० पी/ए/1877387, दिनाक 3-11-1977 की मूलसीमा शुक्क प्रवोजन प्रति श्रीर मुद्रा विनिमय निम्बरण पनि यह की जाती है।

[मि० जे० सी०सी० आई०एण्ड ई०/ए०एन०डी०/एच० **भो०सी०**/223]

(Department of Foreign Trade)

Office of the Dy. Chief Controller of Imports and Exports ORDER

Ahmedabad, the 5th June, 1978

S.O. 1794.—M/s. Kunjbihari Roller Four Mills, Post Box No. 7 Godhra-Baroda highway, Godhra has been granted import licence No. P/A/1877837 dated 30-11-77 for Rs. 20,000 (Rs. twenty thousand only) for its Silk/Nylon/polyester Bolting cloth and grit guase steel plated wire cloth chilled cast iron rollers.

They have applied for duplicate custom copy and exchange control copy of said licence for Rs. 20,000 on the ground that the original custom and exchange control copies have been lost/misplaced without having been registered with any custom authority and utilised at all

In support of their claim applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that custom copy and exchange control copy of licence No. P/A/1877837 dated 3-11-77 have been lost and direct that duplicate licence of custom purpose and exchange control copy of said licence should be issued to applicant.

The original custom copy and exchange control copy of licence No. P/A/1877837 dated 30-11-77 is cancelled.

[No. JCCI&E/AHD/HOV/223]

कां आँ० 1795.—सर्वश्री प्रिस स्टोर, एडवांस सिनेमा के सामने, भद्रा, अहमदाबाद-380001 को लौग के लिए 10,000 रुपए (इस हजार स्पए माल) के लिए ग्रायात लाइसेस सं० पी०/ई/0294873, दिनांक 4-10-1977 प्रदान किया गया वा।

उन्होंने उक्त लाइसेंस की 10,00 रुपये के लिए भीमा शुस्क प्रयोजन प्रति की मनुलिप प्रति जारी करने के लिए इस ग्राधार पर मावेदन किया है कि मूल सीमा शुस्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुस्क कार्यालय में पजीश्वत कराए बिना और बिल्कुल उपयोग में लाए बिना खो गई/ग्रस्थानस्थ हो गई है।

भ्रापने तर्कके समर्थन में मायेदक ने एक लपध-पक्त दाखिल किया है।

मैं संसुष्ट हूँ कि घायात लाइसेंस नं० पी०/ई/0294873, दिसाक $4 \cdot 10 \cdot 1977$ की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि उक्त लाइसेंस की धनुलिपि प्रति घावेदक को जारी की जानी चाहिए घायान लाइसेंस स० पी०/ई/0294873, दिनांक $4 \cdot 10 \cdot 1977$ की मूस सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रह की जाती है।

[एफ० स० 544/ई एल/11035/ए एस 78/डी एफ०/एस एस बाई]

5.0. 1795.—M/s. Prince Store, Opp. Advance Cinema, Bhadra, Ahmedabad 380001 has been granted import licence No. P/E/0294873 dt. 4-10-77 for Rs. 10,000 (Rs. ten thousands only) for Cloves.

They have applied for duplicate custom purpose copy of said licence for Rs. 10,000 on the ground that the original custom copy has been lost/misplaced without having been registered with any custom house and utilised at all.

In support of their claim applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that custom copy of licence No. P/E/0294873 dt. 4-10-77 has been lost and direct that the duplicate licence

of custom copy of said licence should be issued to the applicant,

The original custom copy of licence No. P/E/0294873 dt. 4-10-77 is cancelled.

[File No. 544/EL/1035/AM78/DF/SSI]

कां भां । 1796. — सर्वेशी प्रिस स्टोर, एडवान्स सिनेमा के सामने भद्रा, ग्रहमवाबाद-380001 को लीग के लिए 10,000 रुपयें (दस हजार रुपए मान्न) के लिए श्रायात लाइसेम सं० पी । (ई/0294872, दिनांक 4-10-1977 प्रदान किया गया था।

उन्होंने उक्त लाइसेम की 10,000 रुपये के लिए सीमा शुल्क प्रयोजन, प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस ग्राधार पर ग्रावेदन किया है कि मूल सीमा शृल्क प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराण बिना और बिल्कुल उपयोग में लाण बिना खो गई/ग्रस्थानस्थ हो गई है।

भ्रपने तर्क मे समर्थन से भ्रावेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है।

मै सन्तुष्ट हू कि श्रायात लाइसेय स० पी/ई/029 4872, दिनाक 4-10-1977 की सीमा गुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है श्रीर निदेण देता हूँ कि उक्त लाइसेंस की श्रनुलिपि प्रति श्रावेदक को जारीकी जानी चाहिए।

श्रायात लाइसेंस सं० पी $o/\hbar/0294872$, दिनाक 4-10-1977 की सूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्दे की जाती है।.

[फा० सं० 132/5249डी० एफ०/ए० एम० 78/एस० एस० म्नाई०]

एन० सी० दवे, उप मुख्य नियंत्रक

S.O. 1796.—M/s. Prince Department Store, Opp. Advance Cinema Bhadra, Ahmedabad 380001 has been granted import licence No. P/E/0294872 dt. 4-10-77 for Rs. 10,000 (Rs. ten thousand only) for cloves.

They have applied for duplicate custom purpose copy of said licence for Rs. 10,000 on the ground that the original custom copy has been lost/misplaced without having been registered with any custom house and utilised at all.

In support of their claim applicant has filed an affidavit.

I am satisfied that custom copy of licence No. P/E/0294872 dt. 4-10-77 has been lost and direct that the duplicate licence of custom copy of said licence should be issued to the applicant.

The original custom copy of licence No. P/E/0294872 dt. 4-10-77 is cancelled.

[F. No. 132/5249/DF/AM78/SSI]

N. C. DAVE, Dy. Chief Controller

नई दिल्लो, 5 मृन, 1978

(इलायची नियम्रण)

कार आर 1797.---इलायची नियम, 1966 के नियम 5 के माथ पठित इलायची ग्राधिनियम (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा 3 के खण्ड (ग) के श्रनुगरण में केन्द्रीय सरकार ग्राधिसूचित करती है कि डा० एव० ग्रास्टिन तथा श्री रघुनाथ सिह वर्मा को, जो दोनो लोक सभा के सदस्य है, उस सदन द्वारा उक्त श्रिधिनियम की घारा 4 की उपघारा (1) के भ्रन्तर्गत स्थापित इलायची योर्ड के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया है श्रीर विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त डा० एष० श्रास्टिन तथा श्री रघुनाथ सिह वर्मा इस श्रिधसूचना के राजपल में प्रकाणित होने की सारीख से 3 वर्ष की ग्रवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक वे लोक सभा के सदस्य बने रहते हैं, जो भी पहले हो, उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में पद श्रारण किये रहेगे।

[फा॰ स॰ 32/31/74-प्लांट (बी)] एस॰ महादेव श्रम्यर, उप-निवेशक

New Delhi, the 5th June, 1978 CARDAMOM CONTROL

8.0. 1797.—In pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965) read with rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby notifies that Dr. H. Austin and Shri Raghunath Singh Verma, Members of the House of the People have been elected by that House to be members of the Cardamom Board, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act and specifies that the said Dr. II. Austin and Shri Raghunath Singh Verma shall hold Office as members of the said Board with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of three years or until they cease to be members of the House of the People, whichever is earlier.

[File No. 32/31/74-Plant (B)] S. MAHADEVA IYER, Dy. Director

नई विस्ली, 31 मई, 1978

का० आ० 1798.—-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रिशिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 8(1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के परामर्श से मध्यप्रवेश सरकार के सवर्ग के भारतीय प्रशासन सेवा के ग्रिशिकारी श्री के० जै० एस० भाटिया को 2 मई, 1978 के दोपहर के पहले से ग्राग श्रीर भादेश होने तक के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सिमव के पद पर प्रतिनियक्ति श्राधार केपर नियक्त किया है।

[सं० ए-12011/21/78-प्रशा०1]

New Delhi, the 31st May, 1978

5.0. 1798.—In exercise of the powers conferred by section 8(1) of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (No. 26 of 1962), the Central Government in consultation with the National Cooperative Development Corporation have appointed Shri K. J. S. Bhatia, an J.A.S. Officer of the cadre of Madhya Pradesh Government as Secretary of National Cooperative Development Corporation. New Delhi with effect from the forenoon of 2nd May, 1978 on deputation basis until further orders.

[No. A-12011/21/78-Estt. I]

कार आर 1799.—-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम प्रधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 8(1) द्वाराप्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के परामर्श से मध्य प्रदेश सरकार ने सवगं के भारतीय प्रशासन सेना के प्रधिकारी श्री के जे एस भाटिया का 2 मई, 1978 के दोपहर के पहले से ग्रागे और ग्रादेश होने तक के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सचिव के पद पर प्रतिनियस्ति ग्राधार पर नियक्त किया है।

[स॰ ए॰ 12011/21/78 प्रशा॰ 1] के॰एस॰ बाजका, प्रकरसचिक **S.O.** 1799—In exercise of the powers conferred by section 8(1) of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), the Central Government in consultation with the National Cooperative Development Corporation have appointed Shri K. J. S. Bhatia, an I.A.S. Officer of the cache of Madhya Pradesh Government as Secretary of National Cooperative Development Corporation, New Delhi with effect from the forenoon of 2nd May, 1978 on deputation basis until further orders.

[No. A. 12011/21/78-Estt. I] K. S. BAJWA, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक पृति तथा सहकारिता मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 ज्न, 1978

(इलायबी नियंत्रण)

कां अां 1800. के हीय सरकार, इलायची नियम, 1966 के नियम 3 के उप नियम (1) और नियम 5 के उप-नियम (2) के साथ पिटत इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उप खंड (i) द्वारा प्रवस प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती कोमल धानन्द के स्थान पर श्री एस० महादेव श्रय्यर, उप निदेशक, वाणिज्य मलालय, को नियुक्त करती है और भारत सरकार के वाणिज्य मलालय की श्रीधमूचना स०का० धान 448(श्र), तारीख 26 श्रगस्त, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, श्रथात्.—

उक्त श्राधिसूचना के नीचे की सारणी में कमांक (4) के गामने दूसरे स्तम्भ मे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, श्रथति:---

"श्री एस० महादेव ग्रस्यर, उप निदेशक, बाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।"

> [फाइल सं० 32/20/75—प्लान्ट (बी)] गुक्षीर्य बर्मा, उप गस्विव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Deptt. of Commerce)

New Delhi, the 8th June, 1978

(CARDAMOM CONTROL)

S.O. 1800.—In exercise of the powers conferred by subclause (i) of clause (d) of sub-section (3) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), read with subrule (i) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby appoints Shri S. Mahadeva Iyer, Deputy Director, Ministry of Commerce vice Smt. Komal Anand, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 448(E), dated the 26th August, 1975, namely

In the Table under the said notification, for the entry in the second column, against Serial No. (4), the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri S, Mahadova Iyer, Deputy Director, Ministry of Commerce, New Delhi."

[File No. 32/20/75-Plant(B)] SUDHIR VARMA, Dy. Secy.

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 13 जून, 1978

का अशा । 1801. — के न्द्रोय सरकार, प्रशिम सिववा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के प्रधीन ग्रेन, राईस, प्रायलसीं हुन मर्बेन्ट्स एसोसिएशन बन्धई द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए अधिव पर वायदा बाजार प्रायोग के परामर्थ से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में प्रीर लोक हिन में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त सिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को मृंगफली की गिरियों की अग्रिम सिवाप्रों के बारे में 10 अगस्त, 1978 से 9 अगस्त, 1979 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सिम्मिलत है) की एक वर्ष की धानिरक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस सर्व के स्रधीन है कि उक्त एसो-सिएणन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिए जाए।

> [मि॰सं॰ 12(१)/श्राई॰ टी॰/78] बी॰ श्रीनिशासन, उप सचिव

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 13th June, 1978

- S.O. 1801.—The Central Government, having considered in in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Grain, Rice and Oilseeds Merchants' Association Bombay, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of one year from the 10th August, 1978 to the 9th August, 1979 (both days inclusive) in respect of forward contracts in groundout kernels.
- 2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such direction, as may, from time to time, be given by the Forward Mathets Commission.

[F. No. 12(9)-IT/78]

V. SRINIVASAN, Dy. Secy.

पूर्ति और पुनर्बास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1978

का० आ० 1802.—-निष्कान्त सम्पन्ति प्रशासन प्रधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा(3) द्वारा महाग्रभिरक्षक के क्प में मुझे मौपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्ति श्रौर पुनर्थास मंद्रालय, (पुनर्थान विभाग) की श्रशिसूचना संख्या 1(30)/वि० सेल/75-एस० एस०-2 विनांक 20 मार्च, 1978 का श्रिधिकमण करने हण मैं इसके द्वारा इस विभाग की श्रिधिसूचना संख्या 1(30)/विशेषसेल/ 75-एस० एस०-2 दिनांक 27 मई, 1978 द्वारा राजस्थान,

राज्य के लिए निबुक्त उप महाश्रमिरक्षक की श्री भार० वी० सोक्तके की महाश्रभिरक्षक को निस्न शक्तियां सौंपता है:---

- (1) अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तिया।
- (2) प्रधिनियम की धारा 10(2)(0) के अधीन किसी भी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अस्मोदन की शक्तियां।
- (3) निष्कान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 30-ए के प्रधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां।

[संख्या 1 (30)/विशेष मेल/75-एस०एस-2] गर्गेण मिश्र, महाश्रभिरक्षक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 27th May, 1978

- S.O. 1802.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) and in supersession of the Government of India in the Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) New Delhi Notification No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II dated the 20th March, 1978, I hereby delegate to Shri R. V. Sontake, Deputy Custodian General for the State of Rajasthan, appointed vide this Department's Notification No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. II dated the 27th May, 1978, the following powers of the Custodian General:—
 - (i) Powers under sections 24 and 27 of the Act.
 - (ii) Powers of approval of transfer of any of evacued property under Section 10(2)(0) of the Act.
 - (iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950.

[No. 1(30)/Spl. Cell/75-SS. III] GANGESH MISRA, Custodian General.

नई दिल्ली, 30 मई, 1978

कां० आं० 1803.—निष्कान्त हित (प्रथक्तरण) प्रिष्ठितियम, 1951 (1951 का 64) की धारा 4 की उाधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, निर्माण, प्राथास पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की प्रशिक्षचना संख्या 32013(1)/75-ए० जी० जेड० एस० डब्स्यू०, दिनाक 23 मई, 1977 का प्रधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा सेवा निवृत्त बंदोबस्त श्रायुक्त श्री ए० जी० वासवानी को उक्त प्रधिनियम के प्रधीन सौपे गये शक्तियों का प्रयोग करने तथा कायों को करने के लिए सब शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए सक्षम प्रधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[स॰ 14(6)/77-एस॰एम॰-2]

New Delhi, the 30th May, 1978

S.O. 1893.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 4 of the Evacuee Interest (Separation) Act. 1951 (LXIV of 1951), and in supersession of Government of India in the Ministry of Works, Housing, Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Notification No. 32013(1)/75-AGZ/SW dated the 23rd May, 1977, the Central Government hereby appoints Shri A. G. Vaswani, Retired Settlement Commissioner, as Competent Officer for the Union Territory of Delhi for the purpose of performing the functions and exercising the powers assigned to him under the said Act.

[No. 14(6)/77-SS, II]

(बन्दोबस्त पदा)

नई दिल्ली, 19 मई, 1978

कां आत 1804. — निष्कारत सम्पत्ति प्रशासन ग्रिक्षिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा इस विभाग के बन्दोबस्स विग के बन्दोबस्स विग के बन्दोबस्स विग के उक्त प्रधिनियम लागू होता है, उक्त ग्रिधिनियम के श्रधीन या इसके द्वारा, उप ग्रिभिरक्षक को सोपे गए कार्यों को निष्पावित करने के लिए सरकाल प्रभाव मे, उप ग्रिभिरक्षक के स्प में नियुक्त करनी है।

[स॰ ए॰ 36016(1)/75-एड (जी जैंड)/बन्दोबस्त विग/76] वीना नाथ श्रसीजा, संयुक्त निवेशक

(Settlement Wing)

New Delhi, the 19th May, 1978

S.O. 1804.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950) the Central Government hereby appoints Shri Pritam Singh, Settlement Officer in the Settlement Wing of this Department as Deputy Custodian of Evacuee Property for the States to which the aforesaid Act applies for the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy Custodian by or under the said Act with immediate effect.

[No. A-36016(1)/75-Ad(GZ)/SW/76] D. N. ASIJA, Jt. Director

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विकास)

नई दिल्ली, 27 मई, 1978

कार 1805.—कोककर कीयला बान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 20 की उपधारा (2) के प्रधीन प्रवत्त गक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतव्ह्रारा 15 मार्च, 1978 के पूर्वीह्न से श्री राम बीज राम को सहायक मुगतान ग्रायुक्त नियुक्त करती है।

[सं० 11024/5/78-सी०ए०] जी० बी० जी० रामन, उप सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 27th May, 1978

S.O. 1805.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 20 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government hereby appoints Shri Ram Cheez Ram, as Assistant Commissioner of Payments with effect from the forenoon of the 15th March, 1978.

[No. 11024/5/78-CA] G. V. G. RAMAN, Dy. Secy.

कृषि और सिचाई मंत्रालय

(कृषि विमाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1978

का॰आ॰ 1806.-पशुधन धायात श्रधिनियम, 1898 (1898 का श्रिधिनियम 9) के खण्ड 2 की धारा (क) के धनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतब्द्रारा निम्निलिखित रोग अथवा विकास की उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकामक या छूत के रोग धीयित करती है:---

पशुष्टों के "जीभ नीला रोग" (इस्टूटग)

[सं० 53-18/77 एल० ही ० टी ०-एल० एच० (ए० व्य०)]

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (Department of Agriculture)

New Delhi, the 18th May, 1978

S.O. 1806.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act IX of 1898), the Central Government hereby specifies the following disease to be infectious or contagious disorder for the purpose of the said Act, namely:—

Blue tongue disease of cattle.

[No. 53-18/77-LDT(LH-AQ)]

कां कां 1807. --- प्रमुखन प्रायात शिविनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) के खण्ड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रवल शिव्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जीभ के नीला होने के रोग से प्रभानित किसी भी पणु लपा दाने, चारे, गोबर, घुड़ धाल के कूड़ा-करकट, कपड़े, भण्ड-सण्जा भण्डा पणुक्षन से संबन्धित या उनके सम्पर्क में रखे गए गुड़ जुड़नार के भारत में आयात पर प्रतिबंध लगाती है।

[सं॰ 53-18/77-एल०डी०टी०एल०एस०(ए०न्यू०)] बी०बी० कवूर, उप सचिव

S.O. 1807.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of the Section 3 of Livestock Importation Act 1898 (Act IX of 1898), the Central Government hereby prohibits the import into India of any cattle affected by Blue tongue disease and of any fodder, dung, stable litter, clothing, harness or fitting appertaining to livestock or that may have been in contact therewith.

[No. 53-18/77-LDT(LH-AQ)] B. B. KAPOOR, Dy. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई विल्ली, 8 जून, 1978

का०आ० 1808.— नगर भूमि (भिधिकतम सीमा तथा विनियमन) मिधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 2 के खण्ड (व) के उरवन्त्र के साथ पठित उसके खण्ड (ट) के मनुसरण में केन्द्रीय सरकार इसके साथ उपाबद्ध मनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त भिधिनियम के भावधानों के प्रम्तांत ऐसे कार्यों के लिये जो उक्त धनुसूची के कालम (3) में तबमुक्त्यी प्रविद्धि में दिए गए हैं, सक्षम भिधकारी के रूप मे ऐसे क्षेत्रों के लिये प्राधिकत करती है जो छावनी भिधिनियम, 1974 (1974 का 2) की धारा 3 के भन्तांत छावनी की स्थानीय सीमा क्षेत्र के भन्तांत भोषित किए गए हैं।

वनु सूची

स्यक्ति	छावनी के मन्सर्गत क्षेत्र जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं	भधिनियम के वे उपबन्धा, जिसके प्रस्तर्गत उसे सक्षम प्राधिकारी के कार्यकरने हैं
1	2	3
(i) सेना सम्पदा प्रधिकारी जालन्धर परिमंडल, जालन्धर छावनी	जालन्धर छावनी की स्थानीय सीमाघों के घन्तर्गत इतना क्षेत्र जो जालन्धर नगर समूह क्षेत्र की परिधि में भाता है	·
(ii) कार्यकारी घधिकारी छावनी बोर्ड, जालन्धर छावनी	जालकार छावनी की स्थानीय सीमाक्री के क्रश्नर्गत इनना क्षेत्र को जालकार नगर समूह क्षेत्र की परिधि में घाता है	

1	2	3
(iii) सेना सम्पदा भधिकारी, राजस्थान परिसंदन, जयपुर	श्रजमेर छावती की स्थातीय सीमाझों के अन्तर्गत पूर्ण क्षेत्र	भ्रुठ्यायIII/ ग्रुष्टमामIV की धारा 26 तथा 27-
(iy) कार्यकारी प्रधिकारी, छावनी बोई प्रजमेर छावनी	भ्रजमेर छावनी की स्थानीय सीमाओं के भ्रन्तर्गंत समस्त क्षेत्र	म ≉पाय~ IV की धारा ३०
(v) सेवां सम्पदा भिंधकारी, बिहार परिमंडल, दीनापुर छावनी	दोनापुर छात्रनी की स्थानीय सीमाग्रों के ग्रन्तर्गत समस्त क्षेत्र	ग्रज्याय-III/ प्राच्याय IV की धारा 26 तथा 27.
(vi) कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोब, दीनापुर, छावनी	वीनापुर छावनी की स्थानीय सीमाओं के घन्तर्गेत समस्त क्षेत्र	म्रध्याय IV की भारा 30
(vii) सेना सम्पत्रा श्रधिकारी (नगर भूमि मधिकतम मीमा) भागरा	मोरार छ।वनी की स्थानीय सीमान्नों के भीतर समस्त केंद्र	न माग विक्री/ मान्याय I / 26 तथा 27
(viii) कार्येकारी मधिकारी, छावनी बोर्ड, मोरार	मोरार छावनी की स्थानीय सीमाझों के भीतर समस्त क्षेत	घडवाय IV की धारी 30.
		[एफ॰ सं॰ 12/2/77-यू॰सी॰यू॰]

[एफ सं० 12/2/77-यू असि प्यू०) एस० महादेय प्रस्थर, उप संचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 8th June, 1978

S.O. 1808.—In pursuance of the provisions contained in clause (d) of section 2 of the Urban Land (Coiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), read with clause (K) of that section, the Central Government hereby authorises the persons mentioned in column (1) of the Schedule hereto annexed to perform the functions of the competent authority under the provisions of the said Act specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, for the areas within the local limits of the cantonments, declared as such under section 3 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), specified in the Corresponding entry in column (2) thereof.

SCHEDULE

Регѕод	Areas within Cantonments for which the person is appointed competent authority	Provisions of the Act under which he is to perform the functions of the competent authority
1	2	3
(i) Military Estate Officer, Jull- undur Circle, Jullundur Canton- ment.	So much of the area within the local limits of the Canto- ment of Jullundur as falls within the peripheral area of Jullundur Urban Agglomeration.	Chapter III and Sections 26 and 27 of Chapter IV.
(ii) Executive Officer, Cantonment Board, Jullundur Cantonment.	So much of the area within the local limits of the Cantonment of Jullundur as falls within the peripheral area of Jullundur Urban Agglomeration.	Section 30 of Chapter IV
(iii) Military Estate Officer, Rajasthan Circle, Jalpur.	Entire area within the local limits of the Cantonment of Ajmer.	Chapter III and sections 26 and 27 of Chapter IV.
(iv) Executive Officer, Canton- ment Board, Ajmer Canton- ment.	Entire area within the local limits of the Cantonment of Ajmer.	Section 30 of Chapter IV.
(v) Military Estate Officer, Bihar Circle, Dinapore Cantonmen	Entire area within the local limits of the Cantonment t. of Dinapore.	Chapter III and section, 26 and 27 of Chapter IV.
(vi) Executive Officer, Cantonment Board, Dinapore Cantonment.	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	t Section 30 of Chapter IV.
(vii) Military Esate Officer (Urban Land Ceiling), Agra.	Entire area within the Local limits of the Cantonmer of Morar.	of Chapter III and sections 26 and 27 of Chapter IV.
(vili) Executive Officer, Cantonmen Board, Morar.	t Entire area within the local limits of the Cantonmen of Morar.	t Section 30 of Chapter IV.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई विस्सी, 15 जून, 1978

का अा 1809. — यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्त्य मंत्रालय की 4 जून, 1964 की अधिसूचना सं० एक 16-22/63 एम 1/एम पी टी द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय निकिस्ता परिषद् भिधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनो के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, यू०एस०ए० द्वारा प्रदत्त "एम०बी०" चिकिस्सा अर्हुता मान्य निकिस्सा प्रहुता होगी;

श्रीर यत. डा॰ टी॰सी॰ फियराबैंड जिनके पास उकत श्रर्हता है गैंकिक श्रनुसंधान श्रीर धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल किस्बियन मैंडिकल कालेज तथा बाउन मेमोरियल श्रस्यताल, लुधियाना के साथ सम्बद्ध हैं;

प्रतः, प्रवः, उक्तं प्रधिनियमं की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा —

- (1) सरकारी राजपत मे प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की, अथवा
- (2) उस भवधि को जब तक डा० टी०सी० फियरबैण्ड किश्चियन मैडिकस कालेज तथा बाउन मेमोरियल भ्रस्थताल, लुधियाना के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह भवधि विनिविष्ट करती है, जिसमे पूर्वोक्त डा० मैडिकस प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[सं॰ वो॰ 11016/8/78-एम ई (की)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1978

S.O. 1809.—Whoreas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 16-22/63-MI/MPT dated the 4th June, 1964, the Central Government has directed that the Medical qualification, "M. D." awarded by the Washington University, U.S.A., shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. T. C. Fierabend who posseses the said qualification is for the time-being attached to the Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana, for the purposes of teaching, research and charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (i) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies:—

- (i) a further period of two years from the date of publication of this order in the Official Gazette, or
- (il) the period during which Dr. T. C. Fierabend is attached to the said Christian Medical College and Brown Memorial Hospital, Ludhiana.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/8/78-M.E.(Policy)]

का०आ० 1810. — भारतीय विकित्सा परिषद् मिश्वितियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त गिक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामणें लेने के पश्चात एनद्धारा निदेश करती है कि उक्ष प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए "एम०बी०बी०एस० (यूनिवर्सिटी भाष मरवर्ग), पश्चिमी जर्मनी", की विकित्सा महैता मान्य चिकित्सा महैता होगी।

[संख्या बी०11016/14/78 एम०६०(पी)] श्रार० बी० श्रीनिवासन, उप संचित्र s.O. 1810.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consultation with the Medical Council of India, hereby directs that the Medical Qualification "M.B.B.S. (University of Marburg), West Germany", shall be a recognised medical qualification for the purposes of that Act.

[No. V. 11016/14/78-M. E. (P)]R. V. SRINIVAŞAN, Dy. Secv.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रीलियम विमान)

ধুব্রী-বঙ্গ

नई दिल्ली, 5 जून, 1978

का अात 1811 — भारत सरकार के राजपन्न भाग (ii) खंड 3 उप-खंड (ii) दिनौंक 3 मार्च 1978 की पृष्ठ संख्या 280 पर का ज्या संख्या 149 (ई) के मन्तर्गत प्रकाशित भारत सरकार, मैट्टोलियम रस्तयंक भीर उर्वरक मंत्रालय की प्रक्षिम्चमा संख्या 12020/7/7 प्रोड्क्णन, दिनौंक 3 मार्च 1978 के ध्रधीन गाँव शेवा तालुका ऊरण, जिला कुलावा के धन्तगत निम्नलिखित धनुसूची के स्थान पर नीचे दी गई मनुसूची को पढ़े।

पढ़ें	के f	के लिये			
सर्वेक्षण नम्बर	हेक्टेयर	एमारई	सेंटेयर		
182/6 से 11+17+18+19ए+19की+ 13बी+15की+19	0	18	0		
2 ए					
+19					
182/2 〒 5十12十14十16十16十	a	7 20	o		
2ए 15ए+19ए+19बी 1					
185/16					
10/15	0	00	5		
119/3	0	,06	. 0		
119/3 120/1 (ਆਣੇ)	0	0.1	0		
120/1 (पार्ट)	0 1	,20	0		
182/6 से 11+17+16+19ए+ 19सी	0	, 29	0		
+ 13 时 + 15 旬 + 19 + 19	U	16	0		
183/2 से 5+12+14+16+1 बी+	0	20	0		
19ए 🕂 19बी1	v	20	0		
1870/16	0	00	5		
11/15	0	06	0		
110/3	0	04	0		
120/1ए	0	20	0		
120/1बी	1	29	0		

[मिसिल मं॰ 12020/7/77 प्रोड्ण्यान] एस॰एम॰ वाई नदीम, ग्रवर मचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND

FERTILISER

(Department of Petroleum)

ERRATUM

New Delhi, the 5th June, 1978

SO. 1811.—In the notification of Government of India in India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer No. 12020/7/77-Prod. dated 3rd March, 1978, under S.O. No. 149(E) in the Gazette of Government of India, Part II section 3 sub-section (ii) dated 3rd March, 1978, Page No. 286, Village Shewa, Taluka-Uran, District-Kulaba.

Read			For					
Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare	Survey No.	Hec- tare	Are	Cer tiar	
182/6 to 11+17+18+19A+19D+ 13B+15B+19+19	0	18	0	182/6 to 11+17+18+19A+19D+ 13B+15B+19+19.	0		18	0
$\overline{2A}$ $\overline{2B}$								
182/2 to 5+12+14+16+1B+1C+ 1+13+15A+19A+19B-1.	C) 20	0	183/2 to 5+12+14+16+1B+1C+ 1+13+15A+19A+19B-1.)	20	0
2A				2A				
185/16	0	00	5	187A/16	()	00	5
10/15	0	06	0	11/15	C)	06	0
119/3	0	04	0	110/3	()	04	0
120/1 (Part)	0	20	0	120/1A	C)	20	0
120/1 (Part)	1	29	0	120/1B	1	l — –	29	0

[File No. 12020/7/77-Prod.]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

मई विल्ली, 7 जून, 1978

कारकार 1812.—भारत सरकार की मधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रविश्त किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि मधिग्रहण मधिकार) भिविनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के मस्तर्गत प्रकाशित किया गया गुजरात राज्य के मबागाम तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में वैद्यान स्थल संव पस्थर पोइन्ट से डब्लूव एक आईव धोलका-10 तक पेट्रोलियम के लिए मिंग उपयोग के मधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एव प्राकृतिक गैस झायोग ने उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उप-खंड (1) की धारा (1) में निर्विष्ट कार्य दिनोंक 8-4-75 से समाप्त कर दिया गया है।

श्रतः सब पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि श्रीक्षंत्रहण प्रधिकार) नियम, 1963 के श्रन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-इत्तरा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि प्रधिसूचित करते हैं।

प्रमुस्ची

फ्लेयर पोइन्ट से डब्लू०एच०ग्राई० घोलका-10 तक पाइप लाइन कार्यकी समाप्ति कार्य समाप्ति भारत के गौव का०भा०मं० मक्रालय का नाम राजपत्र में की तिषि प्रकाशन की तिषि 8-4-75 17-12-77 वौठा 3917 पैटोलियम रसायन भ्रीर उनेरक [स॰ 12016/5/78-प्रो॰-1] New Delhi, the 7th June, 1978

S.O. 1812.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Flare Point to W.H.I. at Dholka-10 in Nawagam oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of subsection (1) of section 7 of the said Act on 8-4-1975.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Name of Ministry Village	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer VAUTHA	3917	17-12-77	8-4-75

(No. 12016|5|78-Prod.-I)

का०आ० 1813.—भारत सरकार की प्रिधिसूचना के द्वारा जैमा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रविशित किया गया है और पैट्रोलियम पाईप लाइन (प्रयोगकर्ती के भूमि प्रधिग्रहण प्रधिकार) प्रधिनियम, 1962 के खंड 6 के उपखंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के प्रकल्पवर तेल क्षेत्र में उक्त परिजिष्ट भूमि में वैधान स्थल सं० 203 (अम्के-5) से जी जी एस-6 तक पैट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के प्रधिकार प्राप्त किए गए है।

तेल एव प्राकृतिक गैस धायोग ने उपर्युक्त नियम के खब 7 कं उपखण्ड (1) की धारा (i) में निविष्ट कार्य दिनाँक 28-2-77 से समाप्त कर दिया गया है।

भत. मन पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम 4 (प्रयोगकर्ता के भूमि प्रश्लिप्रहुण मधिकार) नियम, 1963 के मंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्-द्वारा जक्त तिथि को कार्य समाप्ति की निथि मधिस्थित करते हैं:

भनुसूची 203 (अन्के०-5) से जी जी एस-6 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति गौब कार्ये समाप्ति मंझालय का नाम का०ग्रा∘स∙ भारत के राजपत्न में की तियि प्रकाणन की तियि पैटोलियम प्रजोल 3546 19-11-77 28-2-77 [मं॰ 12016/5/78-प्रो॰-**П**]

5.0. 1813.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. No. 203 (Ank-V) to GGS-6 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of subsection (1) of section 7 of the said Act on 28-2-1977.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum	Adol	3546	19-11-77	28-2-77

Termination of Operation of Pipeline from D.S. 203 (Ank-V) to GGS-6

[No. 12016/5/78-Prod.-II]

का आ 1814. — भारत सरकार की घिधसूचना के द्वारा जैसा कि यहाँ संलग्न अनुसूची में प्रविधित किया गया है और पैदोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया गुजरान राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उन्त परिशिष्ट भूमि में बेधान स्थल सं० 206 से जी जी एस - 6 तक पैदोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस धायोग से उपर्युक्त नियम के खंड 7 के उप-खण्ड (1) की धारा (i) में निविष्ट कार्य विनाँक 26-2-77 से समाप्त कर विया है।

भतः भव पैट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि मक्षित्रहण मधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत मक्षम प्राधिकारी एतद्-इति उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि मधिमुचिन करते है।

धनुमूची । 206 से जी जी एस-6 तक पाइप लाइन कार्ये कीं समाप्ति

भंजालय का नाम	गौव	का ्र्या ०सं०	भारत के राजनव में प्रकाशन की तिथि	कार्मसमाप्ति कीतिथि
पैट्रोलियम रसायन ग्रीर उर्वरक	प्रडोल	526	25-2-78	26-2-77

[मं॰ 12016/5/78-प्रो॰-3]]

जी० के० दुवाणी, गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम मधिकारी

S.O. 1814.—Whereas by the notification of Governmen of India as shown in schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. 206 to GGS VI in Ankleyhwar oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of subsection (1) of section 7 of the said Act on 26-2-1977.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline From D.S. 206 to GGS VI

Name of Ministry	Villages	S. O. No.	Date of publication in the Gazetto of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer .	Adol	526	25-2-78	26-2-77
			[No	12016/5/78-ProdIII]
		G. K. DUDANI, Co	impetent Authority Under	r the Act for Gujarat.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई विल्ली, विर्नोक 6 जून, 1978

कां अां 1815.--भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मौजालय के आवेश संख्या एस अगे 3792, विश्तिक 2 विसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूधी में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बस्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाव एसव्हारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में थी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के क्यान्तरों सहिल, जिनका विधरण प्रत्येक के बामने उनक अनुसूधी के कालम 6 में विया हुआ है, स्वीइन्त करती है।

अनुसूची

ऋम सं०	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई (मीटरो में)	श्रावेदक का नाम	निर्माता का माम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिका संबन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनामी की फिल्म है या बाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	в
1, 1	भारतीय ममाचार चित्र संख्या 1,526	245.00	फिल्म प्रभाग, 24,पैंडर रोड, सम्बद्ध-26		"समाचार श्रौर सामयिक घटनाश्रों की" फिल्म ।
2. 9	भारतीय सभाषार चित्र संख्या 1,526 (उत्तरी संस्करण)	298.00	- त दै ज-		"ममाचार भ्रौर सामयिक घटनाम्रों" की फिल्म (उत्तरी सर्किट में प्रवर्णन के लिए) ।
3. 1	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1,526	244.00	तदैव		"समाचार भौर सामयिक घटनाओं" की फिल्म ।
	गरतीय संगचार चित्र सक्या 1,527 (पूर्वी संस्करण)	293.00	~त दैव ~		"समाचार भीर सासयि श घटनाभों " की फिल्म (पूर्वी सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
5. 1	नारतीय समाचार चिन्न संख्या 1,528	250.00	–स वै थ−		"समाचार भौर सामयिक घटनाम्रो" की फिल्म ।
	गरतीय समाचार चिन्न संख्या 1,526 विक्षण संस्करण)	302.00	∼ तदैव–		"समाचार स्त्रौर सामधिक घटनास्रो" की फिल्म। (वक्षिण सर्किट मे प्रवर्णन के लिए)।
7. ¥	नारतीय समाचार चित्र संदेशा 1,529	298.00 *	–तदैव⊶		"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म।
g. ¥	गरतीय समाचार चित्र संख्या 1,530	237.00	तदैव		"समाचार भौर सामयिक घटनाओं" की फिल्म ।
-	गरतीय समाचार चित्र संख्या 1,530 (पश्चिमी संस्करण)	302.00	 त ६ैव ⊸		"समाचार श्रीर सामयिक घटनाश्रों"की फिल्म । (पश्चिमी सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
10.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1,531	242.00	–सर्दैव		"ममाचार भीर सामयिक घटनायों" की फिल्म ।
11.	भारतीय समाचार चिम्न संख्या 1,531	301.00	–त र्दय –		''सन(चार स्रोर स।संयिक घटतास्रों'' की फिल्स
((उत्तरी संस्करण)				(उत्तरी सर्किट में प्रवर्शत के लिए)।
1 2.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1,532	223.00	. <i>−न</i> देव		"समाचार भीर सामधिक घटनाओ" की फिल्म।
13.	भारतीय समाचार चिक्न संख्या 1,532 (पूर्वी संस्कर्ण)	302,00	—तदैव <i>—</i>		''ममाचार क्रोर मामधिक घटनाक्रो'' की फिल्म (पूर्वी मर्किट में प्रवर्णन के लिए) ।

1 2		3	4	5
14. भारतीय समाचार जिल	त्र संख्या 1,533	235.00	फिल्म प्रभाग 24, पैकर रोड, बस्बई-26	"समाचार ग्रौर सामधिक घटनाश्रों" की फिल्म ।
15 भारतीय समाचार चिर (दक्षिण संस्करण)	त्र संख्या 1,333	299 00	ল ই ৰ	''समाचार और सामयिक घटनाक्रो'' की फिल्म (दक्षिण सर्किंट में प्रदर्शन के लिए)।
16. भारतीय सचाचार चिर (पश्चिमी संस्करण)	त्र संख्या 1,534	301.00	~तदैय−	"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म (पश्चिमी क्षेत्र में प्रदर्शन के सिए)।
17. भारतीय समाचार जिल	ग संख्या 1,534	243,00	–तवैव–	"समाचार और सामयिक घटनाओं" की फिल्म
18. भारतीय समाचार चिर		221.00	−त देग −	⊷तवैव
19. भारतीय समाचार चिद्र (उत्तरी संस्करण)		287.00	–तदैव–	''समाचार ग्रौर सामयिक घटनाग्रो'' की फिल्म (उत्तरी सर्किट से प्रवर्शन के लिए) ।
20. भारतीय समाचार चिट	सिंख्या 1,536	226.00	–सर्वेव−	"ममाचार ग्रीर सामयिक घटनाग्रों" की फिल्म (सामान्य रिलीज के लिए)।
 भारतीय समाचार चिद (पूर्वी संस्करण) 	ग संख्या 1,536	302.00	~न्त दैश ~	"सम।चार मौर सामयिक घटनामो" की फिल्म (पूर्वीसिकिट में प्रवर्णन के लिए)।
22. भारतीय समाचार चिर	न संख्या 1,538	211.00	– तदैव−	"समाचार ग्रौर सामयिक घटनाश्रों" की फिल्म ।
 भारतीय समाचार चिर (पश्चिमी संस्करण) 	प्रसंख्या 1,538	303.00	–त दैव	''समाचार ग्रीर सामयिक घटनाभ्रो'' की फिल्म (पश्चिमी क्षेत्र में प्रदर्णन के लिए) ।
24. महिती चिस्न संख्या 2:	70 .	259.08	धनराज महल, ग्राऊंड फ्लोर, गुजरात सरकार छन्नपति शिवाजी मार्ग, बम्बई-३७	"समाचार धौर सामयिक घटनाधो" की फिल्म (गुजरात सिकट में प्रवर्शन के लिए) ।
<u>-</u>				u - 704 c.
25. ए न्यू ईचर घाफ गु र्वा		554.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैकर रोक, शम्मद -26	''बाकुसेंद्री'' फिल्म ।
26. फार्मर्स फेंड स्टेट फार्मर	त	406.00	– स वैय –	"डाकुमेंट्री" फिल्म (ग्रामीण घौर घर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रदर्णन के लिए) ।
27. एग्री एक्सपो 77		392.00	–सर्वेष–	''बाकुमेंद्री'' फिल्म ।
2.6. महिती चित्र संख्या 2	7 1	274.32	गुअरात सरकार, धनराज महल, ग्राउंश्व फ्लौर, छक्रपति शिवाजी मार्गे, बम्बई∽39	"समाचार स्नौर सामयिक घटनाश्रों" की फिल (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए) । 止
29. उत्तर प्रदेश समाचार।	संक्या 43	260,90	सूचना झौर जनसम्पर्क मिदे- भालय, उक्तर प्रदेश, लजनऊ ।	"समाचार ग्रीर सामयिक घटनाग्रो" की फिल्म (उत्तर प्रदेश सर्फिट में प्रदर्शन में लिए) ↓
30. ब्यूटी इन स्थोन		273.91	विलीप दत्त मार्कत बतुल चन्द्रमिल, फिरंगी साजार, कटक (उड़ीसा)	[∵] डाकुमेंद्री" फिल्म ।
31. पत्तम		272.82	श्रमरजीत रानू, 51, सीता स्मृति, तीसरा तल, ठाशुर द्वार रोक, कम्बई-2	" डाकु मेंट्री" फिल्म ।
32 उत्तर प्रदेश समाचार	संख्या 4.4	275,00	निवेशक, सूचना भौर जन- सम्पर्केषिमान, उत्तर प्रदेश सञ्चनक	''समाचार ग्रौर सामयिक घटनाग्रो'' की फिल्म (उत्तर प्रवेश सर्किट में पवर्शन के लिए) ।
 उत्तर प्रदेश समाभार व 	नंबया 45	278,00	सदैब	∽तदैव ~
34. जहां समग्र स्थिर है		318.00	फिल्म प्रभाग, 24, पॅंडर रोड, बम्बई-26	"बाकुमेंद्री" फिल्म ।
35. यू० एण्ड वेट्स एंड मेर्ज	रि	304.00	श्री धर्मेपाल, बंगला सं० 5, नजीरवाडी, जुहु चर्च रो , जुहु, बम्बई-51	तदैय
36. महिसी चित्र संख्या 27	7 2	2 74.32	सहायक सूचना निवेशक, गुजरात सरकार, धनराज	''समाभार घौर सामयिक घटनाक्रों'' की फिल्म (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
			महल, प्रांजन्ड पक्षोर, छन्न- पति, शिक्षाजी मार्ग, अम्बर्ह- 39	

1 2	3	4	5 6
37 पोस्तीकाटी पुतर्निर्माण	304.80	श्रान्ध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम लि०, 'ग्रुह- कल्प' एम०जे० रोड, हैदराबाध ।	''समाचार झौर सामयिक घटनाझों'' की फिल्म (धान्ध्र प्रदेश में प्रदर्शन के लिए)।
38. म्रापरेशन 100	225.00	मैसर्स योगी फिल्म, 12, देवदस्त, बेंबस्टेंब, बांबरा, बम्बई- 50	''शिक्षा संबन्धी'' फिल्म (मामा न्य प्रदर्शन के लिए) ।
39. वापालाल गोज टुकोर्ट	375.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैंडर रोड, बम्बई-26	''शिक्षा संबन्धी'' फिल्म (केवल गुजराती भाषा में प्रदर्शन के लिए)।
40. महिती चिश्न संख्या 273	187.76	सहायक भूचना निदेशक (टी) गुजरात सरकार, धनराज महल, पाउंड फ्लोर, छल्ल- पति शिवाजी महाराज भागे, वस्नई-39	''समाचार भौर सामयिक घटनाभ्रों'' की फिल्म (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
41. डा॰ मोहम्मद इकवाल	581.00	मली सरवार जाकरी, 10, सीता महल, बोमाजी पेट्टि रोड, बस्बई-36	''बाकुर्भेट्री '' फिल्म ।
42. विजली से प्रगति	305.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैबर रोड, बम्बई-26	–নবী¶–
43. इंडियाला माहिले		बी ॰ एस ॰ सुबवेत्त, सूनाइटेड फिल्म मार्टेस, 14, राज हाउस, नाली, नम्बई-18	स र्वेय-
4. भजान स्वतंत्रसा सेनानी	439.00	क्षण्डणस्वामी एसोसिएशन, महारमा गांधी रोङ, शास्त्री नगर, मद्रास । ं	∽नदेव ∽
65. महिली चित्र संख्या 274	205.74	गुजरात सरकार, धनराज महार्स, प्राउत्क फ्लोर, छन्न- पति विवाजी महाराज मार्ग, कम्बर्ध-39	''समाचार ग्रौर सामयिक घटनाकों'' की फिल्ब (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
46. ए सिस्टर फार किंट्टू	401.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैंडर रोड, बम्बई-26	''शिक्षा संबन्धी'' फिल्म (दक्षिण सर्किट मैं प्रदर्शन के लिए) ।
47. मध्य प्रवेश समाचार वर्शन संख्या 14	290.16	सहायक निवेशक, शूचना झौर प्रचार, मध्य प्रवेश सरकार, भोपाल ।	"समाचार घौर सामयिक घटनाथों" की फिल्म् (मध्य प्रदेश में प्रदर्शन के लिए) ।
4.8. मेंटीनेम्स एष्ट सी	402,00	फिल्म प्रभाग, 24, पँचर रोड, बस्बई-26	'' डाकुमें ट्री'' फिल्म (सामान्य प्र दर्धन के लि ए)
49 भाषरेशन एभरपोर्ट	397.00	–तदैव–	स वीव
50. श्रह्म ब्रह्मस्मि	295.44	फिल्म लाईन कारपोरेशन, सिमन स्टूडियो, जिमेन्द्रम	—तदै <i>ष</i> —
51. बाह्याचा कहिराव जाला	303 00	महाराष्ट्र सरकार जिल्म केन्द्र तारदेव रोड, बस्वई-34	"बाक्मेंद्री" फिल्म (महाराष्ट्र सक्तिट में प्रदर्शण के लिए) ।
52. महाराष्ट्र समाचार संख्या 3⁄12	297.00	⊸त र्वेव	''समाचार ग्रौर सामयिक घटनामों'' की फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में मराठी ग्रौर हिन्दी में प्रदर्शन के लिए) ।
53. भ्राकासवाणी	528.00	फिल्म प्रभाग 24, पैंडर रोड, बस्बई-26	"डाकुमेंट्री फिल्म ।
54. वि मनाउन्समेंट	600.00	तदैष	"शिक्षा संयग्धी'' फिल्म (पश्चिम वंगाल सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
_{5.5} . ईनफ [े]	422.00	– तदेष–	''शिक्षा संबन्धो'' फिल्म ।

1 2	3	4	5 6
56. श्रल्युमीनियम	320.65	एच० भ्रार० सरीन, सरीन प्रीडक्शन, 4-पोबार रोड, सांताक्षुज,पश्चिम, अम्बर्ध-54	"ढाकुमेट्री" फिल्म ।
57. ट्राई एड मृथेन	268.00	फिल्म प्रभाग, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	"शिक्षा संबन्धी" फिल्म (म्रर्ध शहरी तथा ग्रामीण सर्किटो में प्रदर्णन के लिए) ।
58. वि रेस	172.00	– तव ैय	''शिक्षा सबन्धी'' फिल्म ।
59ः मसला डाडला नाको गः वार्ट	279.00	–तदैव–	''शिक्षा संबन्धी'' फिल्म (महाराष्ट्र में फ्रर्ध णहरी तथा ग्रामीण सर्किटो मे प्रवर्णन के लिए) ।
60 एंड दैन दि वै डिंग	427.00	<u> </u>	''शिक्षा संबन्धी'' फिल्म (सामान्य प्रदर्शन के लिए)।
61. मशीनवाला	283.00	⊷तदैघ—	''शिक्षा सबन्धी'' फिल्म (हिन्दी सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
62 महिती जिल्ल संख्या 276	192.02	सहायक भूचना निदेशक, गुजरात सरकार, धनराज महल ग्राउन्ड फ्लोर, छत्नपति शिवाजी महाराज भागे, बम्बई-39	"समाचार ग्रोर सामाजिक घटनाग्रो" की फिल्म (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
63. भोलो माटी होरावी गेटी	293.00	सूचना ग्रौर जन सम्पर्क महा- निवेशक, महाराष्ट्र सरकार फिल्म केन्द्र, 68, तारदेव रोड, बम्बई-34	''डाकुमेंट्री'' फिल्म (महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।

[फाइल संख्या 315/1/78-एफ (पी)]

अर्जुन वेष मलिक, डेस्क ग्रधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING ORDER

New Delhi, the 6th June, 1978

S.O. 1815.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First

Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film		Length of the film (in metres)	Name of the Applicant	Name of the Producer	Brief whether a synopsis scienti- fic film or for educational purpose or a film dealing with news current events or documentary films.
1	2		3	4	5	6
1.	INR 1526	•	245,00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"News & Current Events.
2.	INR 1526 (Northern Edition)	٠	298.00	-do-		Release in North circuit, 'News Current Events.
3.	INR 1527		244.00	-do-		"News & Current Events"
4.	INR 1527 (Eastern Edition)	•	293,00	-do-		Release in East circuit, 'News & Current Events'.
5.	INR 1528 .		230 00	-do-		'News & Current Events'.
6.	INR 1528 (Southern Edition)		302.00	-do-		Release in Southern Circuit, 'News and Current Events'.
7.	INR 1529		298.00	-do-		'News & Current Events'.
8.	INR 1530		237 00	-do-		-do-
9.	INR 1530 (Western Edition)	•	302.00	-do-		'News & Current Events' in Western Circuit
10.	INR 1531		242,00	-do-		'News & Current Events'.
11.	INR 1531		301 00	-do-		Release in Northern Circuit, 'News
((Northern Edition)					& Current Euents,

1 2	3	4	5 6
12. INR 1532	223.00	Films Division, 24-Peddar Roac Bombay-26.	'News & Current Events'.
13, INR 1532 (Eastern Edition)	302.00	-do-	Rolease in Eastern circuit 'New & Current Events'.
14. INR 1533	235.00	-do-	'News & Current Events'.
15. INR 1533 (Southern Edition)	299,00	-do-	Release in Southern circuit, 'Nev & Current Events'.
6. INR 1534 (Western Edition)	301.00	-do-	Release in Western region 'New & Current Events'.
17. INR 1534	243.00	-do-	'News & Current Events'.
8. INR 1535	221.00	-do-	-do-
9. INR 1535 (Northern Edition)	287.00	-do-	Release in Northern edition 'Nev & Current Events'.
0. INR 1536	226,00	-do-	General release and classifie
1. INR 1536 (Eastern Edition)	302,00	-do-	'News & Current Events'. Release in eastern circuit and class fied 'News & Current Even
22. INR 1538	211.00	-do-	'News & Current Events'.
23. INR 1538	303.00	-do-	Release in Western region an
(Western Edition)	00,606	-40-	classified as 'News & Curet Events'.
4. Mahiti Chitra No. 270 .	259.08	Dhanaraj Mahal, Gound floor, Govt. of Gujarat, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bom- bay-39.	Release in Gujarat circuit, 'New & Current Events'.
5. A New Year of Goodwill	554.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.	'Documentary'.
Farmer's Friend State Farms.	406,00	-do-	Release in rural & semi-urba areas and classified as 'Docu mentary'.
27. Agriexpo 77	392,00	-do-	'Documentary'.
28. Mahitichitra No. 271 .		Govt. of Gujarat, Dhanaraj Mahal Ground floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-39.	Release in Gujarat Circuit, 'New & Current Events'.
9. Uttar Pradesh Sama- char No. 43.	260,90	Directorate Information & Public Relations Deptt., Uttar Pra- desh, Lucknow.	Release in Uttar Pradesh Circui 'News & Current Events
O. Beauty In Stone .	273.91	Dilip Dutta, C/o Atul Chandra mitra Firingi Bazar, Cuttack (Orissa).	'Documentary'
1. Patan	272,82	Amarjeet Ranu, 51, Sita Suriti, 3rd Floor, Thakurdwar Rd., Bombay-2.	-do-
2. Uttar Pradesh Samachar No. 45.	275.00	Director, Information & Public Relations Deptt., Uttar Pradesh, Lucknow.	Release in Uttar Pradesh circui 'News & Current Events'.
3. Uttar Pradesh Samachar No. 45.	278.00	-do-	-do-
4. Where Time Stands Still .	318.00	24-Peddar Road, Films Division, Bombay-26.	'Documentary',
5. You and Weights and Measure.	304.00	Shri Dharam Pal, Bungalow No. 5, Nazirwadi, Juhu Church Road, Juhu, Bombay-51.	-đo-
5. Mahitichitra No. 272	274.32	The Asstt. Director of Information, Govt. of Gujarat, Dhanaraj Mahal, Ground Floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-39.	'News & Current Events' Release in Gujarat Circuit.
7. Ponnikato Punarnirman	304.80	Andhra Pradesh State Film Development Corp. Ltd., 'Gruhakalpa', M. J. Road, Hyderabad.	Release in Andhra Pradesh 'News & Current Events'.

1 2	3	4	5 6
38. Operation 100	225,00	M/s. Yogi Films, 12 Devdut, Bandstand, Bandra, Bombay-50.	General release 'Educational',
39. Bapalal Goes To Court .	375.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay.	Release in Gujarati language only 'Educational'
40. Mahitichitra No. 273 .	187.76	Asstt. Director of Information (T) Govt. of Gujarat, Dhanaraj Mahal, Gr. Floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay- 39.	Release in Gujarati circuit 'News & Current Events'.
41. Dr. Mohammad Iqbal .	581.00	Ali Sardar Jafri, 10 Sesta Mahal, Bomaji Petit Road, Bombay-36.	'Documentary'
42. Progress With Power .	305.00	24-Peddar Road, Films Division, Bombay-26.	-do-
43. Indiana Mahile		Shri S. Sukhdev, United Film Arts, 14 Rock House, Worli, Bom- bay-18.	-do-
44. The Unknown Freedom Fighters	439.00	Krishnaswamy Associations, Mahatma Gandhi Road, Shastri- Nagar, Madras.	-do-
45. Mahitichitra No. 274	205.74	Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal, Gr. Floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg Bombay-39.	Release in Gujarat Circuit 'News & Current Events'.
46. A Sister For Kittu.	401.00	24-Peddar Road, Films Division, Bombay-26.	Release in Southern Circuit 'Edu- cational'.
 Madhya Pradesh Sama- char Darshan No. 14. 	290,16	Asstt. Director, Information & Publicity, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.	Release in Madhya Pradesh as 'News & Current Events'.
48. Sentinels At Sea	402.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.	General release 'Documentary'.
49. Operation Airport .	297.00	-do-	General release and classified 'Documentary'.
50. Aham Bramasmi		Film Line Corp. Sivan Studio, Trivandrum.	General release and classified as 'Documentary'
 Khandyacha Khanderao Zala 		Govt. of Maharashtra Film Centre, 68- Tardeo Road, Bombay-34.	release in Maharashtra circult and classified as "Documentary"
52. Maharashtra News No. 312.	297.00	Govt. of Maharashtra Film Centre 68- Tardeo Road, Bombay-34.	Release in Maharashtra Circuit and classified; 'News & Current Events' in Marathi & Hindi vesssions.
53. Akashvani	528.00	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.	'Documentary'.
54. The Announcement .	600,00	-₫0-	Release in West Bengal circuit an classiffed 'Educational'.
5. Enough	122.00	-do-	'Educational'
556. Aluminium	320,65	H.R. Sarin, Sarin Production 4, Podar Rd., Santacruz West, Bombay-54.	'Documentary'
57. TryAnd You Can .		24-Peddar Road, Films Division, Bombay-26.	Release in semi-urban and rural circuits 'Educational'. 'Educational'
58. The Race	172,00	-do-	Release in somi-urban and rural
59. Asla Dadla Nako Ga Bai.	279.00	-do-	circuits in Maharashtra, classi- fied 'Educational'.
60. And Then The Wedding	427.00	-do-	General release and classified as 'Educational'.
61. Machinewala	283,00	-do-	Release in Hindi circuits 'Educa- tional'

1	2	3	4	5	6
62. Mahitic	hitra No. 276	192.02	Asstt Director of Information, Govt. of Gujarat, Dhanraj Mahal, Gr. Floor, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay- 39.		Release in Gujarat circuit and classified as "News and Current Events".
63. Oli Mat	i Hirayi Sheti .	293.00	Directorate General of Informa- tion and Public Relations., Govt. of Maharashtra Film Centre, 68-Tardeo Rd. Bombay-34.		Release in Maharshtra circuit as "Documentary".
					[File No. 315/1/78-F(P)]

[File No. 315/1/78-F(P)] A.D. Malik, Desk officer

श्रम मंह्यालय

आवेंश

नई दिल्ली, 25 मई, 1978

कारुआर 1816 — केन्द्राय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध ग्रनुसूबी मे विनिदिष्ट विषयों के बारे मे बीरुसीरुजीर वैक्सिन खैंबोरेटरी, मद्रास के प्रबन्धलंक्ष से सम्बद्ध नियोजको ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीयो-यिक विवाद विद्यमान है;

धौर केन्द्रीय सरकार उक्त विश्वाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेणित करना वाळनीय समझती है ;

श्रतः, श्रव, शौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खर (ध) द्वारा प्रदत्त गांक्तियों का प्रयोग करते हुँथे, केन्द्रीय सरकार एक भौद्योगिक श्रिधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन श्रिधिकारी श्री के०से ह्वारत्नम होंगे, जिनका मुख्यालय, भद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त श्रौद्योगिक श्रिधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देणित करती है।

ग्रनुसूची

"क्या बी०सी०जी०बैक्सिन लैंबोरेटरी, गिंडी, महास के प्रबन्धतंत्र की माकुरी ग्रार० यसन्था, ग्लासवेयर क्लीनर की सेवा को 17-3-76 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नही, तो कुमारी श्रार० वसन्था किस शनुतोष की हकदार है?"

[मं० एल 42012(19)/77-जी०2(बी)] हरजन्स बहाबुर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 25th May, 1978

S.O. 1816.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the B.C.G. Vaccine Laboratory, Madras and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. Selvaratnam shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras in terminating the services of Kumari R. Vasantha. Glassware

Cleaner, with effect from 17-3-1976, is justified? If not, to what relief is Kumari R. Vasantha entitled?"

[No. L-42012(19)/77-D.II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

New Delhi, the 6th June, 1978

S.O. 1817.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court No. 2, Bombay in relation to the Management of Messrs. Shantilal Khushaldas and Brothers Private Limited, owners of Odamol Iron Ore Mine, Margao, Goa, and their workmen, which was received by the Central Government on 1st June, 1978.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

CAMP: PANAJI

PRESENT:

Shri P. Ramakrishna-Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/18 of 1973

Employers in relation to the management of Messrs. Shantilal Khushaldas and Brothers, Private Limited, Owners of Odamol Iron Ore Mine, Margo, Goa.

AND

Their workman Shii Mahadeo Kandolkar.

APPEARANCES:

For the employers—Shri G. R. Srinivasan, Personnel Manager.

For the workman—Shri George Vaz, General Secretary, Goa Mining Labour Welfare Union, Goa.

INDUSTRY: Iron Ore Mines

STATE: Goa, Daman and Diu.

Panaji, dated the 16th May, 1978

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour acting under the powers conferred upon them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication as per their order No. L-26012/8/73-LR.IV dated 12-12-1973:—

"Whether the action of the management of Messrs, Shantilal Khushaldas and Brothers Private Limited, Owners of Odamol Iron Ore Mine Margao (Goa) was justified in dismissing Shri Mahadeo Kandolkar, Mines Mate with effect from the 4th January, 1973? If not, to what relief is he entitled?"

The facts disclosed in the statement of claim filed by the General Secretary of the Goa Mining Labour Welfare Union are that the workman herein worked for 12 years as a mines Mate in the Odamol Iron Ore Mines belonging to M/s Shanti

lal Khushaldas and Brothers (P) Ltd. hereinafter referred to as the Company before he was removed from service. On 8-9-1972 the workman was arrested by the Police on suspicion while carrying a galvanised Iron pipe. On 9-9-1972 the Mines Manager Shri K. Venketachalam gave a police complaint regarding theft of pipe. The Police charge-sheeted the workman for this offence of theft before the Judicial First Class Magistrate Quepem. Even before the criminal case was disposed of the management served a charge-sheet on the workman on 14-10-1972 for the very same offence. He was also kept under suspension from 9-9-1972. A domestic enquiry was held by Shri Ranade, Labour Officer on 2-1-1973. The workman contends that the domestic enquiry conducted before the conclusion of the criminal proceedings being subjudice is illegal. The Enquiry Officer found the workman guilty of this misconduct. On the finding of the Enquiry Officer the Director of the company passed the order of dismissal dated 4-1-1973 against the workman. On 6-7-1973 the J.F.C.M. acquitted the workman of the offence of theft. Soon after the judgement was pronounced the workman issued a notice to the management demanding reinstatement with continuity of service and full back wages. The management declined to do so. Thereupon the matter was referred to the Assistant Labour Commissioner (Central) Vasco-de-Gama on 18-10-1973, the Government is pleased to make this reference.

The management in their written statement stated that the domestic enquiry cannot be said to be illegal merely because it is initiated before the conclusion of the criminal proceedings. They also submit that all the principles of natural justice have been followed by the Enquiry Officer while conducting the present enquiry against the workman. They also submit that the punishment of dismissal is warranted by the standing orders of the company, They pray that this reference may be answered against the workman.

On the above pleadings the points that arise for consideration are:---

- (i) Whether the domestic enquiry is vitiated for any of the reasons mentioned in the written statement?
- (ii) Whether the finding of guilty arrived at by the Enquiry Officer is warranted by the evidence of record?
- (iii) To what relief?

Point (i):

The facts giving rise to this reference are that the workman herein was working as a Mines Mate in the Odamol Iron Ore Mines of the company. On 8-9-1972 at about 7.30 P.M. two Police constables of Colem Police Station who were on patrol duty at Darbandora apprehended the workman herein on suspicion while he was carrying four pieces of galvanished Iron pipe worth Rs. 80. The workman was secured in the Police lock-up soon after his arrest. The next day the Mines Manager Shri K. Venkatachalam who is now said to be no more filed a complaint with the Police stating that the stolen pipe belongs to the company. The Police chargesheeted the workman in C. C. No. 2243/72 before the J.M.F.C. at Quepem. Before the criminal case could come up for trial the company started taking departmental action. It is also alleged that from 8-9-1972 till the order of dismissal was passed on 4-1-1973 the workman was kept under suspension. The Enquiry Officer Shri Ranade (Labour Officer after examining the complainant Shri Venketachalam for the department and the workman for the defence recorded a finding of guilty. On the basis of this finding the Director of the company by his order dated 4-1-1973 dismissed the workman from service. On 6-7-1973 the J.F.C.M. acquitted the workman of the charge of theft. It is contended on behalf of the workman that the departmental enquiry held by the company before the conclusion of the criminal case is illegal. No authority in support of this contention has been cited. In the absence of any such authority I am not inclined to accept this contention. No other infirmity in the procedure followed by the Enquiry Officer has been pointed out. The departmental

witness was examined in the presence of the workman and he was given sufficient opportunity to cross-examine him. The workman was also given an opportunity to lead evidence to establish his innocence. No bias of the Enquiry Officer against the workman has been alleged or established. I therefor hold that the departmental enquiry is not vitiated for any of the reasons mentioned in the statement of claim.

Point (i) held in favour of the management.

Point (ii):

It is next urged on behalf of the workman that there is absolutely no evidence worth the name to support the finding of guilty arrived by the Enquiry Officer. A perusal of the Enquiry Proceedings marked Ex. E-5 shows that there is only the complainant's evidence in support of the case of theft. That evidence being very short may be usefully extracted:

"Mr. K (applicant) stole 20 feet galvanised pipe from the mine on 8th Sept. '72 evening and was caught by the Police authority on 8th Sept. '72 night. On 9th Sept. '72 during my inspection at the mine, I found that 20 feet galvanised pipe belonging to the company is missing. Accordingly on 9th Sept. '72 we lodged complaint with the Police authority, as per routine procedure. The Police authority had already locked him up. Such type of misconduct namely theft of company's property is serious misconduct and we cannot tolerate such misconduct it the establishment."

After recording the complainant's evidence the Enquiry Officer observed as follows:—

"The Enquiry Officer stated to Mr. K (applicant) that the charge 'theft' fraud or dishonesty in connection with the company's business or porperty' is now established on Mr. K. Prima facic and now Mr. K is given opportunity to give his statement and evidence."

Thereafter the workman's evidence which is given below was recorded :—

"I was on duty on 8th Sept. '72 at Odamol Mine. I did not commit theft. I only want to state this much."

The Enquiry Officer submitted the following report finding the workman guilty:

"Mr. Mahadev Kandolkar, Mines Mate, Odamol Mines committed theft of 20 feet galvanised pipe from the mines on 8th Sept. '72 evening and was caught by the Police Authority on 8th Sept., 1972 night. The charge mentioned in the charge-sheet—"Theft, fraud or dishonesty in connection with the company's business or property" has been clearly established on Mr. Mahadev Kandolkar. Mine Mate though he has denied the charge in his statement."

The evidence of the complainant does not show that it was the workman herein that removed the galvanised pipe from the mine. The exact spot from which the pipe was removed is not spoken to. On what basis the Enquiry Officer could say that it was the workman that was responsible for the commission of theft of that pipe is not clear. Reliance is sought to be placed on the statement of the workman in his cross-examination before the Enquiry Officer. To the question put by the Mines Manager, the workman stated

"I showed the stolen pipe to Mines Manager at Police Station."

From this statement there in no warrant whatsoever for imputing the offence of theft to the workman. Even the Enquiry Officer did not do so. The enquiry report and the finding recorded by the enquiry officer show that there is absolutely no evidence whatsoever on the record to sustain the finding of guilty. Shri Sri Nivasen for the management submits that the plea of the workman before the criminal court viz., that on the night in question as he was carrying home some galvanized iron pipe which was lying abandoned 300 metres away from the mine area he was arrested by the Police is sufficient to incriminate him. The plea taken by

the workman before the criminal court and the evidence led by the prosecution and the defence in the criminal proceedings need not be discussed in considering the acceptability of the enquiry officer's report. To see whether the enquiry officer's finding is warranted, we must confine ourselves to the evidence adduced at the time of enquiry and not to the evidence or the plea taken by the workman before the criminal court about six months after the conclusion of the departmental enquiry.

Reference may also be made to the evidence adduced on behalf of the workman before this Tribunal. The workman examined as WW-1 referred to the defence taken by him before the criminal court. He also stated that the enquiry was conducted in Marathi with which language he is not familiar. He says that his mother tongue is Konkani. At the same time he admits that the proceedings were interpreted to him by the B.O's clerk for his benefit. WW-2 Anant Devdas is another employee of the company. He coraborates the evidence of WW-1 saying that the pipe in question was an old and rusted one, lying abandoned beyond the limit of the mine area. He also says that the alleged stolen pipe recovered from the workman was of the size 3/4" diameter whereas the pipe alleged to have been stolen from the mining area was one inch in diameter. It may be stated that the workman's plea that the pipe recovered from him was not the property alleged to have been stolen from the mine found favour with the learned Magistrate for the reason that the diameter of the missing pipe did not tally with that of the pipe recovered from WW-1. On behalf of the management Shri Srinivasan, Personnel Manager of the company is examined. He says that the Enquiry Officer Shri Ranade is no longer in the service of the company and his whereabouts are not known. The complainant Shri Venkatachalam is not alive. He says that he can identify the signature of S/shri Venkatachalam and Ranade on the enquiry proceedings Ex. E-5.

In view of my finding that there is absolutely no evidence worth the name in support of the finding of guilty arrived at by the Enquiry Officer, the said finding may be said to be perverse and unwarranted.

Point (ii) held against the management.

Point (lii):

Shri George Vaz for the workman stated that the workman is not interested in seeking relief of reinstatement, Admittedly he has secured an alternative ob on 17-10-1973 with M/s Fomento and Company as a Mine Mate on a basic salary of Rs. 275 and V.D.A. of Rs. 157.50 per month. Shri Vaz submits that the workman is entitled to payment of gratuity for his 12 years of service in this company before the date of the illegal order of dismissal and also for salary from the date of dismissal till 17-10-1973, the date on which he secured alternative job. He also complains that no subsistance allowance has been paid to the workman from 9-9-1972 till he was dismissed from service on 4-1-1973 after the departmental enquiry during which period according to him he was kept under oral orders of suspension.

For the aforesaid reasons it is held that the management of Messrs Shantllal Khushaldas and Brothers Private Limited. Owners of Odamol Iron Mine, Margao (Goa) was not justified in dismissing Shri Mahadeo Kandolkar, Mine Mate with effect from the 4th January, 1973. Since the workman is not pressing for the relief of reinstatement he will be entitled to arrears of salary from the date of the illegal order of dismissal viz. 4-1-1973 till 17-10-1973 the date on which he secured an alternative job. The workman will also be entitled to arrears of pay from 9-9-1972 till the date of dismissal viz., 4-1-1973 less any amounts already paid to him.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer. [No. L-260128/73-LR. IV/DIIIB] JAGDISH PRASAD, Under Secy.

New Delhi, the 6th June, 1978

S.O. 1818.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the Industrial dispute

between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd. Ramagundam Div. I and their workmen which was received by the Central Government on 2nd June, 1978.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT:

Srl K. P. Narayana Rao, B.A., B.L., Industrial Tribunal, Andhra Pradesh, Hyderabad.

Industrial Dispute No. 27 of 1977

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Divsion-I.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I, Karimnagar District.

Industrial Dispute No. 28 of 1977

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I, Karimnagar District.

APPEARANCES:

- Sri A. Lakshmana Rao, Advocate-for the Workmen.
- Shri D. Gopala Rao, Member, A. P. Federation of Chambers of Commerce and Industries—for the Management.

COMMON AWARD

The Government of India, Ministry of Labour through order No. 21012(4)/76-D-III(B)/D.IV(B) dt. 21-11-1977 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following dispute existing between the Employers in relation to the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division I and their Workmen to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Messra. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I in terminating the services of Sri P. Gattamallu, Tub-Repairing Mistry, Godavari Khani with effect from 27-8-1976 is justified?

If not, to what relief is the concerned workmen entitled?" This reference was registered as Industrial Disputes No. 27 of 1977.

2. The Government of India Ministry of Labour through Order No. L-21012(5)/78-D-III(B)/D-IV(B) dated 23-11-1977 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 the following dispute existing between the Employers in relation to the Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division I and their workman to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Messrs. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I in terminating the services of Sri Muniruddin, Tub-repairing Mistry, Godavari Khani with effect from 27-8-1976 is justified?

If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 28 of 1977.

- 3. In both these Industrial Disputes, notices were ordered to be issued to the parties. The workmen concerned in both these industrial disputes filed claims statements putting forward similar contentions and they are as follows:mallu is the workman concerned in I.D. No. 27 of 1977 and Muniruddin is the workman concerned in I.D. No. 28 of 1977. They were both working as Tub-repairing Mistries. Godavari Khani, Guttumallu entered service in 1964 whereas Muniruddin joined in 1959. Their record of service was un-blemished throughout. On 7-6-1976 both these workmen reported for duty in the first shift which commenced at 7.00 a.m. At about 9.00 a.m. they went to the Canteen for tea. At the Canteen Muniruddin was informed about his wife's serious illness by his son. Both these workmen therefore went to Muniruddin's house and made arrangements to get Muniruddin's wife treated by a private Physician Under these circumstances both these workmen could not attend duty for the rest of the period during the first shift. They were charge sheeted on 7-6-1976 for leaving the workshop without permission and ultimately the punishment of suspension for ten days was imposed on them through a letter dated 30-7-1976. On 13-6-1976 another charge-sheet was issued to both these workmen stating that during the first shift on 8-6-1976 they were caught at about 2.00 p.m. while stealing a brass cable socket. Through another letter dated 15-6-1976 the date mentioned in the charge-sheet was corrected as 7-6-1976. A domestic enquiry was conducted and both these workmen were dismissed from service with effect from 27-8-1976. The domestic enquiry was root and the discountry was root and the d tic enquiry was not conducted impartially and in accordance with the principles of natural justice. The findings arrived at are perverse. The Divisional Superintendent is not competent to pass the impugned orders of dismissal and it is only the General Manager that can dismiss them. These workmen did not commit any misconduct. The punishment of dismissal is dis-proportionate to the gravity of the misconduct. Eversince their dismissal these workmen could not secure alternative employment inspite of best efforts. Under these circumstances both these workmen pray that an award might be passed setting aside the orders dated 26-8-1976 by which they were dismissed from service with effect from 27-8-1976 and directing their reinstatement with full back wages and continuity of service
- 4. In both these industrial disputes the Management filed counters with the following identical allegations.—These workmen left the workspot without the permission of the authority. For that they were chargeshected under Standing Order 16(18) and suspended for ten days. Again both these workmen were further charge-sheeted under Standing Order 16(2) for committing theft of a brass cable socket. An enquiry was conducted into the charge and it was held that the charge was proved. Thereupon both these workmen were finally dismissed. It is false to contend that the domestic enquiry was not conducted in an impartial manner or in accordance with the principles of natural justice. It is also not correct to state that the findings recorded at the domestic enquiry are perverse. The punishment awarded is proper and fair in view of the fact that the past conduct of the workmen was not good. The claims put forward by the workmen are likely to be rejected.
- 5. On 8-3-1978 I passed a preliminary order holding that the principles of natural justice were followed by the officer who held the domestic enquiry and that the findings recorded by him were not prima facie perverse
- 6. In view of the permission accorded to both parties, W.Wa 1 and 2 were examined on behalf of the workmen. W.W.1 Muniruddin is the workman concerned in I.D. No. 28 of 1977 whereas W.W. 2 is Gattumallu the workman concerned in I.D. No. 27 of 1977. On behalf of the Management M.W. 1 who has been working as Foreman in the Workshop at Godavari Khani was examined and Exs. M1 to M3 were marked.
- 7. The case of the workmen as set out in the claims statement and as spoken to by W Ws. 1 and 2 may now be stated Both these workmen were working as Tub-repairing Mistries in the workshop at Godaviri Khani under the Singareni Collieries Company I imited. Ramagundam Division-I. On 7-6-1976 they went for work in the first shift which lasts from 7.00 a.m. to 3.30 p.m. At about 8.30 or 8.45 a.m.

- W.Ws. 1 and 2 went to the Canteen for tea. W.W. 1's 12 years old son by name Azeem came to the Canteen and Informed his father that his mother namely W.W. 1's wite had taken ill. W.W. 1 was upset. He went home along with W.W. 2 and found that his wife's condition was serious. He made efforts till about 12.30 p.m. to raise funds required for obtaining private medical treatment for his wife. Ultimately W.W. 2 pledged his wife's silver anklets with a Marwadi for Rs. 50.00 and made that amount available to W.W. 1. Both the workmen took W.W. I's wife to a private Physician by name Dr. Rajam who gave her an injection. The sick lady was taken home. Both the workmen remained by her bed side without returning to duty for the rest of the shift hours. On the very same day Ex. M1 the charge-sheeted dated 7-6-1976 was served on both the workmen for having absented themselves from workspot from 8.00 a.m. till the end of the shift without permission which is misconduct under Standing Order 16(18). Ex. M2 is the order dated 30-7-1976 passed by the Management suspending both these workmen for ten days from work from 1-8-1976 as a measure of punishment for the above charge. On 13-6-1976 another charge-sheet was served on both these workmen stating that on 8-6-1976 at about 2.00 p.m. both these workmen were caught by two Watchman by name M. A. Hakeem and K. P. James while stealing a brass cable societ of the Lordon K. P. James while stealing a brass cable socket of the Loader Machine, lying by the side of the stone pulverliser machine and that it was a serious offence under Standing Order 16(2). A Memo dated 15-6-1976 was issued by the Management correcting the date of the aforementioned offence given in the charge-sheet as 7-6-1976 instead of 8-6-1976 which was the date originally mentioned. Both these workmen submitted explanations danging the offence in the charge made in the charge ted explanations denying the allegations made in the chargesheet. A domestic enquiry was held into the charge and five witnesses were examined for the Management and four including the two workmen concerned for the charge-sheeted employees. The Enquiry Officer submitted a report to the effect that the charge levelled against both these workmen under Standing Order 16(2) was proved. The Management thereupon passed orders on 26-8-1976 dismissing both these workmen from service with effect from 27-8-1976. These disputes subsequently came to be referred to this Tribunal.
- 8. M.W.1 was examined only to show that he had no personal enimosity against W.Ws. 1 and 2.
- 9. In view of Section 11-A of the I.D. Act, 1947 it is open to this Tribunal to re-appraise the evidence that was already adduced before the Enquiry Officer. On behalf of the Management five witnesses were examined at the domesthe Management live witnesses were examined at the domestic enquiry. Witness No. 1 at the domestic enquiry is no other than the present M.W. 1. He was not a direct witness to the alleged theft of brass cable socket by W.W.1 and 2. All that he stated as that when he went to the tub-repairing section during the hours of the first shift, he did not find either of these two workmen namely W.Ws. 1 and 2 in the Section and that the workshop Charge Hand by name Vecriah informed him that he had learned from some Watchmen that these two workmen had been caught while stealing some brass material by the side of the pulveriser plant. Witness Nos. 2 and 3 at the domestic enquiry are the two Watchmen attached to the Stores and they are alleged to have seen W.W. 1 and 2 trying to take a week the brace of have seen W.Ws. 1 and 2 trying to take away the brass cable socket which was lying near the stone pulverising machine close to the Stores. They deposed at the domestic enquiry that W.W.1 was seen carrying the article in question away while W.W.2 was with him, that on seeing these two Watchmen W.W.1 dropped the article and briskly walked away, that Witness No. 3 examined on behalf of the Management at the domestic enquiry caught W.W. 1 near the pulverising she J but W.W. 1 shook him off and that both the delinquent workmen went to the Tub-repairing Section. It is also their version that Witness No. 5 examined at the domestic enquiry, who is Driver, was called by them and that the Driver saw W.Ws. 1 and 2 going towards the Tub-repairing Section. The two Watchmen further stated that Witness No. 4 examined at the domestic enquiry, who is the Workshop Charge Hand, was also informed about the occurrence and that when the Charge Hand came to the workshop, W.W.2 was seen leaving by a bicycle. The evidence of these five witnesses examined at the domestic enquiry on behalf of the Management is consistent in all material particulars and free from any discrepancies, W.W.1 admitted that he has no animosity against two Watchmen namely James and Hakeem. All that is stated

was that M.W.1 had a quarrel with W.W.2's wife near a street tap. This is denied by M.W.1 and even if it is true, the explanation appears to be too far-fetched to merit acceptance. There is also no acceptable evidence that W.Ws. 1 and 2 had submitted any demand to M.W.1 for categorisation of work etc. and that on that account there are ill-feelings between W.Ws. 1 and 2 on the hand and M.W.1 on the other M.W.1 is also an employee like W.W.s.1 and 2 and it is improbable that the workmen would serve a charter of demands on M.W.1 for categorisation of work etc. Hence the oral evidence adduced on behalf of the Management at the domestic enquiry proves that W.Ws.1 and 2 tried to take away the brass cable socket which was lying near the Loader Machine by the side of the pulverising plant and that on being detected they dropped the article and made good their escape.

10. Certain points urged on behalf of the workmen may now be considered. In the first place it is argued that there are ill-feelings between W.Ws. 1 and 2 on the one hand and M.W.1 on the other and that therefore W.Ws.1 and 2 were implicated in a false charge of theft. I have already negatived this contention. Secondly it is argued that from about 9.00 a.m. till the end of the first shift on 7th June, 1976 both W.Ws. 1 and 2 were attending upon W.W. 1's sick wife at W.W. 1's house and that they could not therefore have gone to the Stores and committed the these and applications. sick wife at w.W. Is nouse and that they could not therefore have gone to the Stores and committed the theft as alleged. At the outset there is no dis-interested evidence except the self-serving testimony of W.Ws. I and 2 that W.W. I's wife was taken to a private Physician by name Dr. Rajam for treatment. Atleast a certificate from Dr. Rajam could have been produced that he had treated W.W. I's wife on 7th June, 1976. It is somewhat unusual that the service of private Physician should have been preferred to those available in the Company's hospital especially when W.W. I did able in the Company's hospital especially when W.W. 1 did not have the required money to pay the private Physician. Apart from the interested testimony of WWs. 1 and 2 there is no evidence that W.W. 2 had pledged the wife's silver anklets with a Marwadi and raised Rs. 50.00 to meet the expenses of the private medical treatment given to W.W. 1's wife. W.W. 2 admits that they did not inform any one about W.W. 1's wife's illness and or that they had taken her to a private Physician for treatment. Hence this contention cannot be accepted. The third contention urged is that when Ex. M 1 was served on W.Ws. 1 and 2 on 7th June, 1976 itself for their unauthorised absence from duty, there is no reason why the charge sheet relating to the much more serious offence namely theft of Company's property was not served on them immediately but was served only on 13th June, 1976. The allegation of theft cannot immediately be accepted and it is quite possible that the Management thought it desirable to make some enquiries to satisfy itself about the need for framing a charge against W.Ws, 1 and 2. That must be the reason why the charge sheet relating to the alleged theft was not served on W.Ws. 1 and 2 on 7th June, 1976 but was served on them six days later. Fourthly it is contended that in the charge the date of the alleged theft as originally mentioned was 8th June, 1976 and that it was subsequently altered to 7th June, 1976 and that this circumstance itself shows that the imputation is false. The date 8th June, 1976 appears to have been mentioned in the charge by mistake and on account of inadvertance. As soon as the mistake was detected it was corrected through an amendment Memo issued on 15th June, 1976. Hence W.Ws. 1 and 2 cannot be allowed to take advantage of this typographical error which crept into the charge regarding the date of the alleged offence. Fifthly it is argued that the brass cable socket is always fastened to the Loader Machine with eight bolts and that it takes a long time to detach it from the machine and that if W.Ws. 1 and 2 had done so they would have certainly been caught while removing the socket from the Loader Machine. The charge is not that W.Ws. 1 and 2 themselves had removed the brass cable socket from the Loader Machine and tried to steal it. On the other hand the charge is that they had committed theft of the brass cable socket lying near the pulverising machine. It is quite possible that somebody had removed the brass cable socket from the Loader Machine and left it lying on the ground nearby and that W.W. 1 tried to lift it and carry it away. Hence nothing turns on this fact. Lastly it is con-tended that since the I oader Machine is close to the pulverising plant, where people would be working and since it also adjoins a road, W.Ws. 1 and 2 could not have ventured to commit theft of the brass cable socket in broad day light namely at about 2.00 p.m. on 7th June, 1976. It is the cyrdence of M.W. 1 that the pulverising machine is installed in a shed whereas the loader machine is in the open space behind the shed. The road is also not a public thorough fare and we cannot expect heavy traffic on it. Hence chances of the theft being detected were very slender and W.Ws. 1 and 2 might have felt confident that they would be able to carry away the brass cable socket without being detected or caught red handed, Hence I am unable to accept any one of the contentions urged on behalf of the Workmen.

- 11. From all these circumstances it is clear that at about 2.00 p.m. on 7th June, 1976 W.Ws. 1 and 2 themselves attempted to steal the brass cable socket from near the pulverising machine and that their attempt was folled by the vigilance of the two Workshop Watchmen. It therefore follows that the misconduct covered by Standing Order 16(2) is proved against W.Ws. 1 and 2.
- 12. Standing Order 16(c) lays down that in awarding punishment the Manager shall take into account the gravity of the misconduct, the previous record if any of the employee and any other extenuating or aggravating circumstances that may exist. It is not clear whether the previous record of service of W. Ws. 1 and 2 was considered before the punishment of dismissal was imposed on them. Merely because they absented from duty on 7th June, 1976, it does not automatically follow that their record of service is so bad as to justify the imposition of the extreme penalty of dismissal. It was a case of attempted theft which did not frustify. If at all it was only W.W. 1 that tried to carry away the brass cable socket. The evidence of the witnesses examined by the Management at the domestic enquiry does not show that W.W. 2 had any hand in it. His mere presence at the place when W.W. 1 attempted to carry away the article need to the inference that he also actively participated in the offence. At any rate it does not appear as if W.Ws. 1 and 2 had ever been found guilty of misconduct on any prior occasion. I am of the opinion that though the misconduct alleged is proved the punishment of dismissal imposed on them is not justified under these circumstances and that W.Ws. 1 and 2 should therefore be reinstated.
- 13. It has been held in Management of M/s. D. B. R. Mills Limited v. Rayamayya and another (W.P. No. 2040/76 dated 1st August, 1977 reported in Judicial Index of the Decisions of the High Court of Andhra Pradesh Part IX, September, 1977 at page 142) as follows:—
 - "It is not therefore necessary in view of this provision that the Tribunal must arrive at a finding regarding unfair labour practice or victimisation. Even if no victimisation or unfair labour practice is proved, it is open to the Labour Court or the Tribunal to award lesser punishment in lieu of discharge or dismissal if it is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified. The Tribunal may well come to the conclusion that though the order is not regularly vitiated in that the domestic enquiry was properly conducted, the order of dismissal was not justified because it was two severe."

Another decision that may be referred to in this context is the one reported in District Manager, A.P. S.R.T.C. v. Labour Court, Guntur (Reported in 1978 Andhra Pradesh High Court Notes page 1) wherein it was held as follows:—

"It is clear from the decided cases that while dealing with a dispute referred to it under the Industrial Disputes Act, the Tribunal has a very wide discretion in awarding punishments to the workmen and it cannot be confined only to the penaltics specified in the Regulations or Standing Orders of the particular management. The Tribunal is at perfect liberty to impose such reasonable and rational punishment as it thinks necessary and appropriate under the circumstances of a particular case. In imposing punishments while the powers of the managements are regulated by the Rules and Standing Orders of the managements, the industrial adjudicative authorities are not controlled by any such Rules or Standing Orders. The adjudicative authorities impose punishments by reference to the paramount consideration

of industrial peace, which is the essence of industrial adjudication. A direction withholding the payment of back-wages either fully or partly has since long been recognised as a punishment in industrial adjudications."

Lastly reference may be made to the following passage occurring at page 550 of Malhotra's Commentary on the Law of Industrial Disputes (Second Edition, Volume I):—

"Apart from directing reinstatement of a discharge or dismissed workman these adjudicatory authorities have also been given the power to subject the order of reinstatement to any terms and conditions which they may think fit on the facts and in circumstances of a case. For instance, the Tribunal may direct that the workman on reinstatement will be entitled to the payment of full wages, partial wages at all for the period from the date of discharge or dismissal till the date of reinstatement."

W.W. 1 states that he was making out his livelihood by working in a Cinema Theatre whereas W.W. 2 states that he has been making a living as a Lorry repairer ever since the date of their dismissal. The income they get through this means is very much less than the salary which they were getting at the time of their dismissal. But since I have come to the conclusion that the misconduct alleged against W.Ws. 1 and 2 is proved but that the punishment of dismissal is not justified, I am of the opinion that, in view of the principles laid down in the decision referred to above, the entire back wages should be dis-allowed to W.Ws. 1 and 2 and that it is enough if their reinstatement alone is ordered.

- 14. I, therefore, hold that though the misconduct alleged against W.Ws. 1 and 2 is proved, the order of dismissal passed against them is not justified and that W.Ws. 1 and 2 should therefore be reinstated with continuity of service. This is subject to the condition that W.Ws. 1 and 2 shall not be entitled to any back wages from the date of their dismissal till the date of their reinstatement.
 - 15. A common Award is hereby passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th day of May, 1978.

APPENDIX OF EVIDENCE

WITNESSES EXAMINED FOR WORKMEN:

W.W. 1 Sri Muniruddin.

W.W. 2 Sri P. Gattamallu.

FOR MANAGEMENT:

M.W. 1 Sri R. K. Sinha.

DOCUMENTS EXHIBITED FOR WORKMEN:

Nil.

DOCUMENTS EXHIBITED FOR MANAGEMENT:

- Ex. M1 By Consent: Charge Sheets No. EE/WS/9/662 dated 7th June, 1976 issued to Sri P. Gattumallu and Muniruddin by the Management.
- Ex M2 By Consent: Dismissal Order No. EE/WS/9/ 994 dated 30th July, 1976 issued to Sri P. Gattumallu and Muniruddin by the Management.
- Ex. M3 By Consent: Domestic enquiry files of Sri P. Gattumallu and Muniruddin.

Sd/- Illegible, Presiding Officer [No. L-21012(4)/76-D.III(B)/D.IV(B)] BHUPENDRA NATH, Desk Officer नई दिल्ली, 9 जून, 1978

का०आ० 1819.—यतः केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा मधि-नियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (ग) के अनुसरण में श्री एस० वासुदेवन के स्थान पर श्री एन०के० पण्डा, संयुक्त सिव्ध, भारत सरकार, वित्त संशालय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है;

भतः ग्रंब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा ग्रंधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के भनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रासय की मिधसूचना संख्या का॰भा॰ 1517 तारीख 14 मंत्रेल, 1976 में निम्नसिखित संशोधन करती है, भर्षात्.—

उक्त प्रधिभूचना में, "[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (ग) के प्रधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षंक के नीचे भद 7 के सामने की प्रविश्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, प्रयोत.—-

"श्री एन० के० पण्डा, संयुक्त समित्र, भारत सरकार, वित्तमंत्रालय, नर्ष विल्ली"

> [सं॰ यू॰ 16012/10/76 एच॰ प्रार्ष॰] एस॰ एस॰ सहस्रानामन, उप सचिव

New Delhi, the 9th June, 1978

S.O. 1819.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (c) of section 4 of the Employees' State Insuance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri N. K. Panda, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, as a member of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri S. Vasudevan.

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely:—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the Central Government under clause (C) of section 4]", for the entry against item 7, the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri N. K. Panda,

Joint Secretary to the Government of India.

Ministry of Finance,

New Delhi.

[No. U-16012/10/76-HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 9th June, 1978

S.O. 1820.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Birsinghpur Colliery of Western_Coalfields Ltd. and their workmen which was received by the Central Government on 6th June, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

PRESENT:

Shri S. N. Johri, B.Sc., LIM., Presiding Officer

Case No. CGIT/LC(R)(17) of 1977

Employers in relation to the Management of Birsinghpur Colliery of Western Coalfields Limited, District Shahdol (M.P.) and their workman Shri Vijay Singh, Badli Mazdoor of Birsinghpur Colliery PO. Birsinghpur Pali, Distt. Shahdol (M.P.).

APPERANCES:

For Management-Sri P. S. Nair, Advocate.

For Workmen-Sri G. C. Jaiswal.

INDUSTRY: Coal Mines DISTRICT: Shahdol (M.P.)

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's order No. L-22012(5)/77-D-IV(B) dated 26-8-1977, for adjudication of the following industrial dispute:

"Whether the action of the Management of Birsinghpur Colliery of Western Coal Fields Ltd., District Shahdol, in stopping Shri Vijay Singh, Badli Mazdoor of Birsinghpur Colliery from work vide letter No. BRS/96/4004 dated 30-10-1976 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

Following facts constituted the charge of gross misconduct that was levelled against Sri Vijay Singh, Water Spraying Badli Mazdoor in Birsinghpur Colliery.

- 2. When on 9-2-1976 he completed the spraying of Pit Bottom in No. 35 Landing Sri Ram Gopal in-charge asked him to go to development district for fitting hand pump in 51 Dip/61L face which was full of water. He refused to do the work. Sri Ram Gopal then sent him to Sri Mahipal Singh, General Shift Overman of Development Section, who asked him to do at least stone dusting but he refused to do even that work and left the section at about 11.00 A.M. Next day no work was allotted to him. He made complaints and asked for duty from Sri P. K. Singhai, Assistant Manager, who was standing outside his office. After some talk he is alleged to have given a shoe beating to Shri P. K. Singhai. Assistant Manager, and further slapped him on the face. Shri N. P. Gupta, Safety Officer, Birsinghpur Colliery, conducted the enquiry on that charge. On the basis of his report the appointing authority held that the charge was proved against him and by way of punishment stopped him from work.
- 3. This Tribunal held vide order dated 22nd April 1978 that the domestic enquiry was properly held, proper opportunity to defend was given to the delinquent and the findings of the enquiry officer were not perverse. The facts constituting the charge were fully proved.
- 4. Even though the parties did not raise the question of reasonableness of quantum of sentence yet that issue was framed because even otherwise this Tribunal has jurisdiction to examine the quantum aspect. Neither side alleged or produced any evidence of extenuating or aggravating circumstance. To give shoe beating to an Assistant Manager and slap him on the face on the work sight is an act of grossest misconduct which should call for the highest penalty of dismissal from service. I therefore see no reasonable ground for interfering with the punishment. The Award is given accordingly.

Jabalpur, May, 30th 1978

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[L-22012(5)/77-D-IV(B)]

New Delhi, the 12th June, 1978

S.O. 1821.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Chirlmiri Ponri Hill Colliery, Post Office, Chirimiri, District Surguja and their workmen which was received by the Central Government on 9th June, 1978.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT JABALPUR (M.P.)

PRESENT

Shri S. N. Johri, B.Sc., LL.M. Presiding Officer.

Case No. CGIT/LC(R)(19)/1977

PARTIES:

Employers in relation to the management of New Chirimiri Ponri Hill Colliery, Post Office, Chirimiri, District Surguia (M.P.) and their Workmen represented through the President, M. P. Koyala Mazdoor Panchayat, P. O. Kurasia, District Surguja (M.P.).

APPEARANCES:

For Union-Shri Hardeo Singh.

For Management—Shri B. K. Sinha, Personnel Officer and Shri Dhar.

INDUSTRY: Coal Mines DISTRICT: Surguja (M.P.)

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's Order No. 22012(10)/76-D.III(B)/D-IV(B) Dated 26th October, 1977, for the adjudication of the following industrial dispute with respect to the contract labourers named in the Annexure to this award:

- "Whether the demand of the Union for payment of wages to the mine car loaders mentioned in the Annexure, of New Chirimiri Ponri Hill Colliery of CIL, Post Office Chirimiri District Surguja, at the rate prescribed for staking and truck loading etc., in the National Coal Wage Agreement with effect from 1-1-1975 is justified ? If not to what benefit are the said mine car loaders entitled ?"
- 2. It is not disputed that these labourers were employed by the Contractor, Shri Naha Roy, who was employed to do the job of transporting the coal from Seam No. 1. The process as explained by the then Assit. Manager, Shri N. S. Shiledar, was that from the Seam No. 1 the coal was transported in dumpers. When the wagons were not available the dumpers dumped the coal by the side of the rail track meant for mine cars (tubs). These contract labourers loaded the mine cars by shovalling operation. The mine cars then trasmed to the Tippler where they were unloaded. The Tippler by an automatic process loaded the wagons.
- 3. The case of the Union is that this loading of the mine cars, tramming then to tippler point and unloading them there or staking, was done by these contract labourers. According to National Coal Wage Agreement on the analogy of truck loading and staking rates prescribed thereunder, they should have been paid @ Rs. 9.45 per mine car of 100 Cft. i.e. 2.5 tonnes, while the contractor paid them @Rs. 4.15 i.e. Rs. 5.29 less per tub. The workers were retrenched on 7-5-1975. The Union therefore claims difference of wages @Rs. 5.29 per tub from 1-1-1975 to 7-5-1975 according to the number of tubs loaded trammed and unloaded for staking.
- 4. The contractor, Shri Naha Roy, was added as a party to the reference but he did not file any written statement. The case therefore proceeded exparte against him.
- 5. The management of New Chirimiri Ponri Hill Colliery filed a reply denying that these contract labuorers were workmen under Industrial Disputes Act. There was no employer-employee relationship between it and these workers. There was no occassion for a dispute between them and the reference is bad on that account. They did not avail of the remedies open to them under Contract Labour Act nor raised any voice till the contract was subsisting. The Union had no representative capacity and no resolution for raising such a dispute was ever passed. The workmers were not the member of the Union. No demand was made with the management and whatever demand was raised before the Asstt.

Labour Commissioner was altogether different from the demand incorporated in the order of reference.

- 6. Unrebutted evidence of the Union proves that about more than 50 per cent workers of the Coliery including those contract labourers were the members of the Union in terms of it's constitution. The Union had in fact passed a resolution for raising this dispute though the constitution empowers the President to raise any such dispute. The objections of the management on these points have thus no force.
- 7. So far as the objection of absents of employer employee relationship between these workmen and the management of New Chirmiri Ponri Hill Colhery is concerned the evidence goes to show that the contract was for doing a specific job or for producing a given result. The labourers recruited by the contractor. They were paid by him and the work was allotted to them by the contractor. Only he had the administrative control over them. Thus they were the contractor's employees.
- 8. The management cannot however escape liability simply because they were the employees of the contractor. S. 21 (4) of the contract labour (Regulation and Abolition) Act 1970 runs as follows:—
 - "In case the contractor fails to make payment of wages within the prescribed period or makes short payment, then the Principal employer shall be liable to make payment of wages in full or the unpaid balance due, as the case may be to the contract labour employed by the contractor and recover the amount so paid from the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt payable by the contractor."

This Sub-section exhibits the anxiety oof the legislature to provide maximum security of wages to the contract labour. It incorporates a principal which is akin to subrogation. By providing that the default of the contractor makes the management directly liable for proper payment of the wages or unpaid balance as the case may be, it thereby creates a fictional direct relationship of employer and employee for that limited purpose of wages. These labourers thus become fictional 'workman' within the meaning of S. 2(s) of Industrial Disputes Act. They are the members of the Union. Threfore the Union is entitled to raise industrial dispute about rate of wages on their behalf.

- 9. The delay in raising the dispute is not of much consequence. Shri Hardeo Singh said that the dispute could not be raised till the contract was subsisting as the workers were teared of him and apprehended termination of employment against which no social security was provided by any law. Sub-S (4) of S. 21 of Contract Labour Act authorities, the principal employer to deduct the amount which it is so required to pay to contract labourers by way of wages or arrears etc. It further provides that the same can as well be recover from the contractor as 'debt'. The fomer situation envisages raising of the dispute either during the subsistence of the contract or before the refund or security while the later provision authorising it to realise the amount as debt envisages raising of the dispute even after the refund of security deposits etc. by the contractor. Thus the provisions of Sub-Sec. (4) of S. 21 does envisage and approve or condono the delay in raising the industrial dispute by or on behalf of the contract labourers. The delay has thus no fatal consequences on the validity and unintainability of the reference.
- 10. Union did raise the dispute with the management as Shri Hardeo Singh did address a letter to the Area General Manager. In any case the dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner in which management participated and denied the demand without raising any such plea. The management is thus estopped from denying that no dispute was raised before it. In any case by the donial of the management to concede the demands before Asstt. Labour Commissioner, an industrial dispute did come into existence before the reference was made. The plea of reference before the reference was made. The plea of reference before that the dispute raised before the management or Asstt. Labour Commissioner was different to the dispute referred to this Tribunal.

- ment the factual position about nature and quantum of work with nave to be assessed for determining the rate at which the payment should have been made. So far as the nature of work is concerned shift N. S. Shiadar (M.W. 1) Assistant manager of new Children Ponti Hill Colnery has given a graphic picture. According to him the tubs were only 3½ in merght the coal staked by the dumper by raining was to be loaded by these workmen in the mine car (tubs) by shovelling process. This was the only duly performed by these contract labourers. The tranning of the mane cars unloaded this into the tippler by an automatic process. No manual labour was required for that purpose. This work of loading the mine cars by shovalling process was very different from the work of loading the truck or staking the coal. In truck loading process the coal has to be taken on head load from the coal heaps to the point where the truck is about 8 Hz. from the ground and, therefore, a wooden plank is placed right from the ground to the truck body for habing the workmen to lide on it and reach the top of the truck. This wooden plank is called enally. After ascending that height on the chally the head load had to be discharged in the truck body where another person makes, it uniform for proper loading. These head load baskets are filled with the coal at the coal heap point by another workman. Thus in that process of truck loading three workmen are involved. The distance travelled is different and the height is much more comparatively. The height of about 8 Ft. has to be ascended on the chally and there the head load has to be dicharged. All this process is absolutely wanting in loading the mane cars by more shovelling process.
- 12. However, even though the two processes are materially different yet in my opinion the amount of labour involved is not very different in the two cases. If the labourer in the case of mine car loading has not to travel a distance with a head load or has not to ascend a chally, his hand would be constantly busy in shovelling the coal into the mine car. The process of shovelling will be more frequent rather continuous and may even tire out the labourer. Thus whether head and feet are involved or the hands are involved it makes little difference so far as the manual labour is concerned. It is a manual labour that is required to be remunerated in terms of money and I think the manual loading process whether it is of truck or of mine car, whether three persons are involved in the process or one workman has to do it by continuous efforts which may tire him out, should not mean much difference so far as the wages are concerned.
- 13. However, let us forget the analogy for the time being and advert to paragraph 41, Section C, Chapter VIII, page 71, Volume I of the Wage Board recommendations for a more apt analogy. That paragraph may be reproduced as under:
 - "It was brought to our notice that in querries there is also a system by which labourers are asked to load while dressing is done by other time or piece rated dressers. We would call this category of workmen quarry labourers. It is clearly understood that their duty is to load coal into tubs only. We would place this category also in Group IV and its workload should be slightly higher than that of an underground labourer and we would fix 2-1/3 tubs of 36 cft. each i.e. 84 cft."

Both quarry loaders and these contract labourers loaded the mine cars. May be that some times the quarry loaders may be required to nagotiate a small distance with a head load for reaching the mine car from the point where dressing is done but the work as defined does not take that aspect into consideration. Their duty was only to load the mine ear and that too of only 84 cft while the duty of these contract labourers was to load the mine car of 100 cft. This difference in the capacity of tub may well cut across the small distance if any the quarry loaders were required to travel from dressing point to the car. On the basis of this apt analogy these contract labourers should be paid wages as are paid to the quarry loaders.

14. The quarry loadets are placed in Group IV and from 1-1-1975 under National Coal Wage Agreement their corresponding wage is Rs. 11.59. As against that the Union claims

only the corresponding wage of group III. More than the claimed wage difference cannot be allowed. Hence it is just that the Management should pay the difference @ Rs. 5.29 claimed by the Union,

15. The Management is thus duty bound under Section 21(4) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 to pay at least the claimed difference of Rs. 5.29 per mine car to these contract labourers according to the number of tube they leaded. On each particular day the number of tubs they loaded on each particular day, the account of which is admittedly with the Management. The Award is given accordingly.

ANNEXURE

(Case No. CGIT/LC/(R)(19)/1977)

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

List showing the names of Mine Car Loaders of New Chirimiri Ponri Hill Colliery of C.I.L., Post Office Chirimiri District Surguja (M.P.) mentioned in Government of India, Ministry of Labour, New Delhi order No. L-22012(10)/76-D-III(R)/D-IV(R) dated the 26th October 1977 III(B)/D-IV(B) dated the 26th October, 1977.

- 1. Sri Jangal Sai
- 2. Sri Matukdhari
- 3. Sri Karmoo Ram
- 4. Sri Ramdhanl
- 5. Sri Lachhmi
- 6. Sri Moharsai
- 7. Sri Goumtu
- 8 Sri Rai Singh
- 9. Smt. Shanti
- 10. Smt. Pearo Bai
- 11. Smt. Muneshari
- 12. Smt Man Bai-I
- 13, Smt. Man Bai-II
- 14. Smt. Man Kaur
- 15. Smt. Gedi-I
- 16. Smt. Fulbasia
- 17. Smt. Gedi
- 18, Sri Jujhar Singh
- 19. Sri Gageshar
- 20. Sri Bahadur 21. Sri Fulsharl
- 22. Sri Gurbari
- 23. Sri Falshari-II
- 24 Sri. Sobhani
- 25, Sri, Makhan
- 26. Srl Amor Sal

S. N. JOHRI, Presiding Officer

I-6-1978

[L-22012(10)/76-D. III (B)/D. IV (B)]

BHUPENDRA NATH, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 1978

का०आ० 1822.--केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा मधिनियम, 1948 (1948 का 34) की घारा 8 के खण्ड (ख) के प्रनुसरण में, श्री एस० वासुदेवन के स्थान पर श्री एन० के० पण्डा, समुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के सबस्य के रूप में नामनिविष्ट किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 8 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या का०प्रा० 477(ड) तारीख 16 जुलाई, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्.--

जनत अधिसूचना में [केन्द्रीय सरकार द्वारा घारा 8 के **खण्ड (ख**) के मधीन नामनिदिष्ट] शीर्षक के नीचे भद 4 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, ग्रर्थात्.--

"श्री एन०के० पण्डा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई विल्ली।"

> [यु॰ 16012(10)/76-एच॰ भारि॰] एस० एस० सहस्रानामन, उप सिषय

New Delhi, the 12th June, 1978

S.O. 1822.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (b) of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri N. K. Panda, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, as a member of the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri S. Vasudevan.

Now, therefore, in pursuance of section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 477(E), dated the 16th July, 1976,

In the said notification under the heading "[Nominated by the Central Government under clause (b) of section 8]", for the entry against item 4, the following entry shall be substituted, namely :-

"Shri N. K. Panda, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, New Delhi.

[No. U-16012(10)/76-H.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई विल्ली, 14 जून, 1978

कां आ 1823. केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी ग्रधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भिधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में स्फतीयाश्म (फेल्स-पार) खानों में नियोजन को जोड़ती है जिसके भाषाय की सूचना, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की, तारीख 12 नवम्बर, 1977 के राज-पत्न में प्रकाशित अधिसूचना सं० का० आ० 3508 तारीख 25 अक्तूबर, 1977 द्वारा, पहले ही वी जा चुकी है।

> [फा॰ सं॰ एस॰ 32019(21)/76-डब्स्यू सी (एम डब्स्यू)] हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 14th June, 1978

S.O. 1823.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act, the employment in felspar mines, notice of its intention to do so having already been given by the notification of Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3508, dated the 25th October, 1977 published at page 3943 of the Official Gazette dated 12th November, 1977.

[File No. S-32019(21)/76-WC(MW)] HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14 जून 1978

का० आ० 1824.— केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐगा करना अपेक्षित था भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (इ) के उप-खण्ड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० भा० 3971 तारीख 9 दिसम्बर, 1977 द्वारा सिक्युरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 विसम्बर, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा भोषित किया था।

भीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की भौर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना भपेक्षित है;

मतः, मन, भौधोगिक भ्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (इ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त प्रक्षित्यम के प्रयोजनों को 18 जून, 1978 से छः मास की भीर कालावधि के लिए लोक उपयोगी लेखा सेवा घोषित करती है।

[सं॰ एस॰ 11017/10/78-हो॰ 1(ए)]

New Delhi, the 14th June, 1978

S.O. 1824.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 3971 dated the 9th December, 1977, the Security Paper Mill, Hoshangabad, to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th December, 1977;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 18th June, 1978.

[No. S. 11017/10/78/DI(A)]

का आ 1825. के जीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (इ) के उपखण्ड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के अम मंद्रालय की अधिसूचना संख्या का बाव 4025 तारीखा 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना के भधीन दुग्ध प्रवाय उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 22 विसम्बर, 1977 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

भौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की भौर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना मधेक्षित है;

श्रतः श्रवः, श्रीजोगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ह) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त एक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त धिरियम के प्रयोजनों के लिए 22 जून, 1978 से छः मास की श्रीर कालाबिध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11019/11/78-डी० 1(ए)]

S.O. 1825.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry Labour No. S. O. 4025 dated the 13th December, 1977, the

industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22nd December, 1977; And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 22nd June, 1978.

[No. S. 11017/11/78/DI(A)]

काठका० 1826.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (इ) के उपखण्ड (VI) के उपबंधों के श्रनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की श्रधिसूचना संख्या का० श्रा० 4024 तारीख 13 दिसम्बर, 1977 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 2 के खण्ड(ख) में यथोपरिभाषित बैंकिंग कंपनी द्वारा जलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को उक्त श्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर, 1977 से छ: मास की कालाविध के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

भीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की भीर कालावधि के लिए बढ़ाय। जाना भ्रमेक्षित है;

मत: भव, भौधोगिक विवाद भिश्तियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के आण्ड (इ) के उपखण्ड (VI) के परन्युक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 जून, 1978 से छः मास की भौर काला-विध के लिए लोक उपयोगी सेया घोषित करती है।

[सं० एस० 11019/12/78-दी० 1(ए)]

S.O. 1826.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry Labour No. S. O. 4024 dated the 13th December, 1977 the Banking Industry carried on by a banking company as defined in clause (bb) of section 2 of the said Act, to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 29th December, 1977;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 29th June, 1978.

[No. S. 11017/12/78/DI(A)]

प्रावेश

मई दिल्ली, 15 जून, 1978

का०आ। 1827.—भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम भीर पुनर्वास मंत्रालय की मधिसूचना का० मा० संख्या 456 विनांक 5 फरवरी, 1963 द्वारा गठिन श्रम न्यायालय, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, के पीठासीन मधिकारी का पद रिक्त हो गया है;

प्रतः प्राव, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपवन्धों के धनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री कें० पद्मनाभ गौढ को पूर्वोदत गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन प्रधिकारी नियुक्त करती है।

[सं॰ एस॰ 11020/5/78-डी॰ 1(ii)]

एल० के० नारायणन, डैस्क धधिकारी

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1978

S.O. 1827.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Hyderabad constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S. O. 456 dated the 5th February, 1963;

Now therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri K. Padmanabha Goud as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S. 11020/5/78/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

New Delhi, the 13th June, 1978

S.O. 1828.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Dalmia Cement (Bharat) Ltd., Dalmiapuram and their workmen, which was received by the Central Government on 26-5-78.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B.A., B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Madras, the 27th April, 1978

Industrial Dispute No. 32 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of M/s. Dalmia Cement (Bharat) Limited, Dalmiapuram).

BETWEEN

The workmen, represented by

The General Secretary, Dalmia Cement National Workers' Union, Dalmiapuram, Tiruchirapalli District.

AND

M/s. Dalmia Cement (Bharat) Limited, Dalmiapuram, Tiruchirapalli District.

REFERENCE:

Order No. L. 29012/13/77-D. III(B), dated 2-6-1977 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for hearing upon perusing the reference and all other material papers on record and upon hearing of Thiru I. M. Moinuddin, General Secretary of the Union and of Thiruvalargal M. R. Narayanaswami and S. Jayaraman, advocates for the Management and memorandum settling the dispute having been received from the union and recording the same, this Tribunal made the following.

AWARD

This is a reference by the Government of India under Section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of the disputes between the Management of Dalmia Cement (Bharat) Limited, Dalmiapuram and their workmen in the matter of non-employment.

(2) The reference is as follows:-

"Whether the Management of Dalmia Cement (Bharat)
Limited, Dalmiapuram was justified in dismissing the
following workmen viz. (i) Sri M. Natarajan, T. No.
192; (ii) Shri M. Ramaswamy, T. No. 5; (iii) Shri
Keeranur Periaswamy, T. No. 11; (iv) Shri Chinnakampatty Ramaswamy, T. No. 29 and (v) Shri
R. Natchimuthu, T. No. 521 from service with effect
from 12th October, 1976?

If not to what relief the said workmen are entitled to?"

- (3) No Claim Statement was filed by the workmen who initiated the reference. When the matter came up for enquiry on 27-4-1978 the General Secretary of the Union who was present before this Tribunal represented that all the five workmen were reinstated and the matter was settled. The management of the Dalmia Cements (Bharat) Ltd. filed a letter stating that the matter had already been settled out of court and the wokers concerned had also been reinstated in service with effect from 1-10-1977.
- (4) In view of the fact that the matter had been settled and the workers had been reinstated in service, no relief is granted under the reference. The reference is closed.

Dated, the 27th day of April, 1978.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer [No. L-29012/13/77-D. III(B)]

मादेश

मई दिल्ली, 15 जून, 1978

कां कां 1829.— केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावक अनुसूची में विनिर्विष्ट विधयों के बारे में मैसूर सीमेंटस लिमिटेश, अमा-सन्दरा के प्रवंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विश्वामान है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिए निर्देशित करना बांछनीय समझती है।

श्रतः, मब, मौद्योगिक विवाद प्रिप्तिनयम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क मौर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (भ) द्वारा प्रदत्त ग्राक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक मौद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीम अधिकारी भी एस० एक० एफ० ऐलवरस होंगे, जिनका मुख्यालय बगलौर में होगा भौर उक्त विवाद को उक्त भौद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

प्रनुसूची

"क्या मैसूर सीमेंटस एम्पलाइज एसोसियेशम की मैसूर सीमेंट लि॰ की खानों में (क) लाइम स्टोन ढोने मौर तोड़ने के लिए सामान्य कार्य-मार का पुनर्नियतन (ख) सामान्य कार्यभार ऊपर वर्षित (क) के मनुसार न्युनतम गारंटिड मजबूरी का नियतन की मांगें न्यायोचित हैं ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस मनुतोष के मधिकारी हैं भीर किस तारीख से ?"

[सं० एल० 29011/11/77-डी**॰ प्री बी०**]

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1978

S.O. 1829.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mysore Cements Ltd., Ammasandra and their workmen in respect of the matter specified in the Schedulc hereto annexed;

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which

Shri S. L. F. Alveres shall be the Presiding Officer, with head-quarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demands of the Mysore Coments Employees'
Association for (a) Re-fixation of the norms of work-loads for breaking and loading of Limestone and (b)
fixation of Minimum guaranteed wages, based on the
norms of the work-load as per (a) above, in the
quarries of Mysore Coments Ltd. are justified? If
not, to what relief are the workmen entitled and from
which date?"

INo. L-29011/11/77-D.III.B.]

भादेश

कां आं 1830—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावध धनुसूची में विनिर्विष्ट निषयों के बारे में मैससे डालिमया सीमेंट (भारत) लिभिटेड, डालिमियापुरम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक ग्रीधोगिक नियाद विद्यमान है;

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना बांछनीय समझती है।

भतः, भ्रवः, भौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क श्रौर धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवत्त कारित्यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक भौद्योगिक धिंध-करण गठित करती है, जिसके पीठासीन धिंधकारी श्री के० सेस्वारत्मम होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा श्रौर उक्त विवाद को उक्त श्रौद्यो-गिक श्रीधकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशिन करसी है।

धनुसूची

"क्या सर्व श्री एम० देवासगायम, पी० थियागराजन, के० राजी छौर ए० धमालवास, केशर मिस्तीयो को डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, डालमियापुरम में थेड IV में लगाने की डालमिया सीमेंट नेशनल वर्कर्स युनियन, डालमियापुरम की माग न्यायोधित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस धनुतीय के अधिकारी हैं ?"

[सं॰ एख॰ 29011/15/78-डी III बी]

ORDER

S.O. 1830.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of M|s. Dalmia Cement (Bharat) Limited, Dalmiapuram and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And Whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri K. Selvaratnam as Presiding Officer with Headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Dalmia Cement National Workers Union, Dalmiapuram for placing S|Shri M. Devasagayam, P. Thiagarajan, K. Rajy and A. Amaldoss, Crusher Maistries in the Dalmia Cement (Bharat) Limited, Dalmiapuram in Gr. IV is justified?". If not, to what relief the concerned workmen are entitled?".

[No. L-29011]15|78-D.III.B]

S.O. 1831.—In pursuance of section 17 of the Indusrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Diamond Mining Project, Panna and their workmen, which was received by the Central Government on the 6-6-78.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(21)/1978.

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Diamond Mining Project, Panna and their workmen represented by Panna Hira Khadan Mazdoor Sangh, N. M. D. C. Colony, Panna (M.P.).

APPEARANCES:

For Union.—Shri D. S. Tiwari, General Secretary.

For Management-Shri S. K. Rao, Advocate.

INDUSTRY: Diamond Mine. DISTRICT: Panna (M.P.)

Dated May 29, 1978

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide it's order No. I.-29025]7|77-D. III.B. Dated 1-5-1978 for adjudication of the following dispute by this Tribunal:

"Whether the action of the Management of National Mineral Development Corporation Ltd., in transferring Shri D. S. Tiwari, Accounts Assistant, vide order No. MIR/Misc/76 dated 8-11-76 from Panna to Kumarswamy is pustified ? If not to what relief the employee in entitled?"

2. Parties arrived at a settlement on 27th May, 1978 after the reference was made and after the notice was issued to them fixing this day for filing written statement. Mainly the dispute was about the transfer of the General Secretary, Shri D. S. Tiwari, which order has been revised and cancelled by the management in terms of the settlement. There is thus no dispute left between the parties. The terms of the settlement are verified. Award is given accordingly. The settlement shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

FORM-H

[See Rule 58 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957].

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Name of Parties :

- $_{\rm i}$ (a) Representing Employer (National Mineral Development Corporation Limited).
- 1. Shri P. L. Jadia, Project Manager, Diamond Mining Project, National Mineral Development Corporation Limited, Panna (M. P.).
- 2. Shri K. V. Rao, Dy. Financial Adviser, Diamond Mining Project, National Mineral Development Corporation Limited, Panna (M. P.).
- 3. Shri T. Sudarsanam, Asstt. Personnel Manager, Diamond Mining Project, National Mineral Development Corporation Limited, Panna (M. P.).
- (b) Representatives of Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria, Panna (M. P.).
 - 1. Shri D. S. Tiwari, General Secretary.
 - 2. Shri Bhopal Singh, Organising Secretary.
- 3. Shri K. G. K. Nair, Treasurer. Short Recital of the Case:
- Shri D. S. Tiwari, Assistant (Accounts), Diamond Mining Project, Panna had been transferred to Kumaraswamy Iron

Ore Investigation vide Assistant Personnel Manager, National Mineral Development Corporation Limited, Hyderabad's office order no. MIR Misc 76, dt. 8th November, 1976. Shri Tiwari had been relieved of his duties from Panna Project on the afternoon of 17th November, 1976. Subsequently Shri D. S. Tiwari had also drawn transfer TA|DA amounting to Rs. 4375 (Rupees four thousand three hundred seventy five only) for himself and his family for going to Kumaraswamy, on 18th November, 1976.

Subsequently the Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria raised an industrial dispute over the transfer of Shri D. S. Tiwari to Kumaraswamy alleging victimization vide their letter no. 1897 dt. 7th December, 1976 addressed to the Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur. On the industrial dispute raised by the Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria, the Assistant Labour Commis-Mazdoor Sangh, Ramkheria, the Assistant Labour Commissioner (Central), Jabalpur had seized this matter in joint discussions which was followed by a conciliation between the management of Diamond Mining Project, National Mineral Development Corporation Limited, Panna, and National Mineral Development Corporation Limited, Hyderabad and the representatives of Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria. The conciliation taken by the Assistant Labour Commissioner (Central), Jabalpur on the industrial dispute raised by Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria over the alleged victimisation had ended in a failure. The Assistant Labour Commissioner (Central) Jabalpur has submitted over the alleged victimisation had ended in a failure. The As-eistant Labour Commissioner (Central) Jabalpur has submitted his failure of conciliation report to the Secretary to Govern-ment of India, Ministry of Labour, New Delhi vide his letter no. J-5 (2)|77-ALC, dt. 29th October, 1977. Subsequently, Shri D. S. Tiwari has made a representation to the Managing Director, National Mineral Development Corporation Limited, Indianal Computer of the transfer order. Hyderabad on 17-4-1978 for cancellation of his transfer orders on humanitarian considerations. Following this, the matter has been discussed by the representatives of the management of Diamond Mining Project, National Mineral Development Corporation Limited, Panna on its own behalf and on behalf of National Mineral Development Corporation Limited, Hyderabad with the representatives of Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria. In the meantime, the following Industrial Dispute has been referred to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur for adjudication vide order no. L. 29025 7 7 D. III. B., dt. 1-5-1978 from the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

"Whether the action of the Management of National Mineral Development Corporation Limited, in transferring Shri D. S. Tiwari, Accounts Assistant vide order no. MIR|Misc|76, dt. 8-11-76 from Panna to Kumarswamy is justified? If not to what relief the employee is entitled?".

After a great deal of discussions between the representatives of the management of Diamond Mining Project, National Mineral Development Corporation and the representatives of Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria which commenced before the dispute has been referred for adjudication, the following settlement has been arrived at to the mutual satisfaction of both the parties, today the 27th May, 1978.

TERMS OF SETTLEMENT:

It has been agreed by the parties to the dispute that-

- (i) The orders of transfer issued to Shri D. S. Tiwari vide National Mineral Development Corporation Limittd, Hyderabad's office order no. MIR/Misc/76, dt. 8th November, 1976 will stand cancelled on the date he reports for duty at Diamond Mining Project, Panna.
- (ii) Shri D. S. Tiwari, would be allowed to join duties at Panna as an Assistant (Accounts) in Finance Department which was the post held by him prior to his transfer.
- (iii) Shri Tiwari, has expressed his unreserved regrets to the management of National Mineral Development Corporation.
- (iv) Absence from 18th November, 1976 till he reports for duty in Finance Department, Diamond Mining Project, Panna, will be regulated duly adjusting

the leave at his credit as on 17-11-1976 (afternoon), os under :-

- (a) 18-11-1976 to 18-1-1977—Earned leave with full pay.
- (b) 19-1-1977 to 4-3-1977—Half pay leave.
- (c) 5-3-1977 till the date of his joining in Pauna Diamond Mining Project in terms of this settlement— Extraordinary leave without pay.
- (v) Shri Tiwari would refund full amount of transfer TA and DA drawn by him for himself and his family amounting to Rs. 4,375 (Rupees four thousand three hundred and soventy five only) drawn at the time of his transfer to Kumaraswamy, in number of equal instalments as decided by the management commencing from the salary of the month in which he joins in terms of this settlement.
- (vi) The said industrial dispute which is raised by the Panna Heera Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria will thus stand withdrawn in so far as the parties to the dispute are concerned as the matter has been fully and finally settled to the mutual satisfaction of both the parties to the settlement.
- (vii) The parties to the dispute will file this settlement before the Honourable Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur and a prayer will be made to give an award in terms of this settlement dated 27th May, 1978.
- (viii) Both the parties will also send copies of this settle-ment to the Secretary to Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, the Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur and the Assistant Labour Commissioner (Central), Jabal-
- (xi) Both the parties further agree that Shri D. S. Tiwari will be taken on duty at Panna Diamond Mining Project immediately after the award is given by the Honourable Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur.

Representatives of Diamond Representatives Mining Projects, National Heera Mineral Development Corporation Limited.

Sd/-(P. L. Jadia) Project Manager.

Sd/-(K. Vithal Rao)

Dy. Financial Adviser. Sd/-

(T. Sudarsanam) Assistant Personnel Manager. Treasurer.

σf Panna Khadan Mazdoor Sangh, Ramkheria.

\$d/-

General Secretary.

(D. S. Tiwari)

(Bhopal Singh) Organising Secretary.

Sd/-(K. G. K. Nair)

WITNESSES:

- Sd/- (L. R. Thareja) Section Officer (I.R.) N.M.D.C. Ltd., Hyderabad.
- 2. Sd/~ (N. P. Rao)

Section Officer Diamond Mining Project; N.M.D.C. Limited, Panna (M.P.).

Dated 27th May, 1978.

S. N. JOHRI, Presiding Officer [No. L-29025/7/77-D.III.B] JAGDISH PRASAD, Under Secy.

29-5-1978

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

काँ० आ० 1832.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्रीमृद्रण, 40 शिवनारायण दास लेन, कलकत्ता-6, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक श्रौर कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रौर प्रकीण उपबंध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागृ किए जाने चाहिए;

भत., भ्रब, उक्त श्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त गत्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

New Delhi, the 15th June, 1978

s.o. 1832.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis. Sreemudran, 40, Shibnarayan Das Lane, Calculta-6 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1977.

[No. S. 35017(15)/78-PF-II]

का० आ० 1833 — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैं सर्स इण्डस्ट्रियल इक्बीपमेंट कम्पनी, प्लांट सं० 4, जवाहर कोग्रापरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड, कमोठ, तालुक पनवेल जिला कोलाबा, जिसमें इसकी खटाऊ बिल्डिंग 130 जे शंकरपेठ रोड, गरिगांव, मुम्बई-4 स्थित शाखा सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रौर कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रौर प्रकीर्ण उपबध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः, धवः, उक्त घधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1 भन्नैल, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [सं०एस० 35018(14)/78-पी०एफ० II]

S.O. 1833.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Industrial Equipment Company, Plot No. 4, Jawahar Cooperative Industrial Estate Limited, Kamothe, Taluk Panvel, District Kolaba including its branch at Khatau Building, 130, J. Shankarsheth Road, Girgaon, Bombay-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

[No. S. 35018(14)/78-PF. II]

का० आ० 1834. — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दिदेसु कैमिकल्स (प्रा०) लिमिटेड, प्लाट सं० 234-ए, जवाहर कोग्रापरेटिय इण्डस्ट्रियल एस्टेट, कमोठ पनवेल, जिला कोलाबा जिसमें हमकी (1) जॉली मेक्स वैम्बर्स सं० 1, सातवीं मंजिल, 68/ए नरीमन प्लाईट, मुम्बई-21, (2) कैलाग्रानगर, 658, तारदेव मार्ग, सुम्बई-7 स्थित साखाएं सम्मिलत हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रौर कर्मचारियो की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिष्ठिय निधि ग्रौर प्रकीण उपबंध ग्रीधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भ्रतः, श्रवः, उक्त प्रधिनियम की धारा । की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रथोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

यह श्राधिस्**व**ना 1 मई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [मं०एस० 35018(18)/78-पी०एफ० **II**]

S.O. 1834.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mcssrs. Didesu Chemicals (Private) Limited, Plot No. 234-A, Jawahar Cooperative Industrial Estate, Kamothe Panvel, District Kolaba including its branchees at (1) Jolly Maker Chamers No. 1, 6th Floor, 68/A, Natiman Point, Bombay-21, (2) Kailash Nagar, 658, Tardeo Road, Bombay-7, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into torce on the first day of May, 1976.

[No. S. 35018(18)/73-PF. II]

का० आ० 1835.—यता केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, स्वर्ण बादेकर बिल्डिंग, पोस्ट प्राफिस बाक्स सं० 31, वास्कोडिंगामा, गोवा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी मिविष्य निधि और प्रकीण उपबंध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

श्रतः श्रवः, उक्तः श्रिशिनियमं की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्तं शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अश्रिनियम के उपबन्धा उक्तं स्थापन को लागु करती है।

यह भिधिसूचना 1 भन्नैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [सं० एस० 35018(32)/78-पी० एफ० **II**]

S.O. 1835.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Bandekar Brothers (Private) Limited, Suvarna Bandekar Building, Post Office Box No. 31, Vasco-da-Gama. Goa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018(32)/78-PF. II]

कां आ 1836—-यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मादाकोम बैर माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुवर्ण बान्देकर बिल्डिंग, पोस्ट ग्राफिस बाक्स सं० 31, वास्को-डा-गामा, गोवा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक श्रौर कर्मकारियों की बहुसंख्या इस बात पर सह्मत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निश्चि श्रौर प्रकीर्ण उपबंध श्रीधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने वाहिए;

श्रतः श्रव, उक्त श्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

यह म्रधिसूचना 1 भ्रमैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [सं० एम० 35018(33)/78-पी० एफ० II]

S.O. 1836.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Madachem Bat Mines (Private) Limited, Suvarna Bandekar Building, Post Office Box No. 31, Vasco-da-Gama, Goa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35018(33)/78-PF. II]

का॰ आ॰ 1837— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससं कोकण ट्रेडिंग कम्पनी, डा॰ कोस्टा पेरेरा बिल्डिंग, म्युनिसिपल स्क्वायर, 'पोस्ट बाक्स सं॰ 302, मारगाम्रो, गोवा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भौर कर्मचारियों की बहुसक्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपबंध श्रीधनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

म्रतः म्रब, उक्त मधिनियम की धारा । की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रशिमूचना 1 जुलाई, 1975 को प्रवृक्त हुई समझी आएगी। [स॰ एस॰ 35018(34)/78-पी॰ एफ॰ II]

S.O. 1837.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Konkan Trading Company, Dr. Costa Pereira's Building, Municipal Square, Post Office Box No. 302, Margao, Gao, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1975.

[No. S. 35018(34)/78-PF. II]

का॰ आ॰ 1838—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर सट्रेक्चर (प्राह्मेट) लिमिटेड, फटोर्दा, मारगाश्रो, गोदा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि घीर प्रकीण उपबंध ग्रिधिन्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

श्रतः भ्रम, उक्त श्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) श्रारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपजन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

यह प्रधिसूचना 1 प्रक्टूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [स॰ एस॰ 35018(35)/78-पी॰ एफ॰ II]

S.O. 1838.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Super Structures (Private) Limited, Fatorda, Margao, Goa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1976.

[No. S. 35018(35)/78-PF. II]

कां आं 1839—पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रादर्श सहकारी ग्राहक संस्था लिमिटेड, मारगाप्रो, गोवा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर प्रकीर्ण उपवध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

मतः मत्र, उक्त मिमिनियम की भ्रारा 1 की उपभारा (4) द्वारा प्रवस गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त मिमिनियम के उपगन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह भिष्मुचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [स॰ एस॰ 35018(36)/78-पी॰ एफ॰ II]

S.O. 1839.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Adarsh Sahakari Grahak Saunatha Limited, Margao Goa, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June 1976.

[No. S. 35018(36)/78-PF. II]

कां आ 1840 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससं भाषिरिया डांक एण्ड स्टील कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, लक्ष्मी नारायण निवास, म्युनिसिपल मार्केट के सामने, वास्को-डी-गामा, गोवा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबुष्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

श्रातः श्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपद्यारा (4) द्वारा प्रवस गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

 S.O. 1840.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Shaparia Dock and Steel Company (Private) Limited, Laxminarayan Nivas, Opposite Municipal Market, Vasco-da-Gama, Goa, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1976.

[No. S. 35018(37)/78-PF. II]

काँ० झाँ० 1841.— फेन्द्रीय सरकार कर्मवारी भविष्य निधि और प्रक्तीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवत्त मिलियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में मावस्यक जाच करने के पश्लात् 31 ग्रगस्त, 1976 से मैसर्स गापरिया डोक एण्ड स्टील कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, लक्ष्मी नारायण निवास, म्युनिसियल मार्केट के सामने, वास्को डा गामा, गोवा, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं॰ एस॰ 35018(37)/78-पी॰ एफ॰ II(ii)]

S.O. 1841.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifics with effect from the thirty-first day of August, 1976, the establishment known as Messrs. Shaparia Dock and Steel Company (Private) Limited, Laxminarayan Nivas, Opposite Municipal Market, Vasco-da-Gama, Goa, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(37)/78-PF. II(ii)]

कां बा 1842 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स होल सेल कनजुमर्स कोग्रापरेटिव स्टोर लि॰, ग्रयना बाजार, शिवपुरी (म॰ प्र॰) जिसमें (1) शिवपुरी (2) पुरानी शिवपुरी, शिवपुरी (3) कमलागंज, शिवपुरी (4) करेरा, शिवपुरी (5) पहारी शिवपुरी (6) बाटानाबार, शिवपुरी (7) कोलारेश, शिवपुरी मौर (8) पिछोन शिवपुरी, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध निशोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविषय निधि और प्रकीण उपबंध ग्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

ग्रतः ग्रव, उक्त मिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त मिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

यह श्रिधसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [सं० एस० 35019(28)/78-पी० एफ० II)

S.O. 1842.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Whole Sale Consumers' Co-operative Store Limited, Apana Bazar, Shivpuri (Madhya Piadesh) including its branches at (1) Shivpuri, (2) Purani Shivpuri, Shivpuri, (3) Kamalagani, Shivpuri, (4) Karera, Shivpuri, (5) Pahari, Shivpuri, (6) Batanabar, Shivpuri, (7) Kolarash, Shivpuri and (8) Pichhoni, Shivpuri, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019(28)/78-PF. II]

कां० आ० 1843 यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससं उड़ीसा कार्ड बोर्ड बाक्स इन्डस्ट्रीज, बी 18, इन्डस्ट्रियल एस्टेट, भूवनेश्वर 10 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि धौर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

्र श्रतः श्रव, उक्तं श्रधिनियम को धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [स॰\एस॰ 35019 (63)/78-पी॰ एफ॰ II(i)]

S.O. 1843.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Orissa Card Board Box Industries, B-18, Industrial Estate, Bhubaneswar-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35019(63)/78-PF. II(i)]

का० आ 1 1844 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परम्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में प्रावश्यक जाच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1978 से मैंसर्स उड़ीसा कार्ड बोर्ड बाक्स ट्रन्डस्ट्रीज, बी-18 इनडस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेश्वर 10, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिधिष्ट करती है।

[सं॰ एस॰ 35019(63)/78 पी॰ एफ॰ II(ii)]

5.0. 1844.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1978 the establishment known as Messrs Orissa Card Board Box Industries, B-18 Industrial Estate, Bhubaneswar-10, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(63)/78-PF. II(ii)]

का० आ० 1845 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि मैसर्सं वी रिजनल स्टेशन, केरल लाइव स्टाक डेबलपमेंट एण्ड मिस्क मार्केटिंग बोर्ड लिमटेड कुलाथुपुजा (केरल लाइव स्टाक डेवेलपमेंट एण्ड मिस्क मार्केटिंग बोर्ड लिमटेड, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय: 9/1148, सस्थामंगलम्, विवेन्द्रम को इकाई) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर प्रकोण उपबंध

भ्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

भ्रतः श्रम, उक्त भिधिनयम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रक्त माक्तयो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त भ्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस॰ 35019 (81)/78पी॰ एप॰ II(i)]

S.O. 1845.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Regional Station, Kerala Livestock Development and Milk Marketing Board Limited, Kulathupuzha (Unit of the Kerala Livestock Development and Milk Marketing Board Limited, Registered Office: 9/1148, Sasthamangalam, Trivandrum), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1978.

[No. S. 35019(81)/78-PF. II(i)]

भा० आ० 1846 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि धीर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में श्रावण्यक जाँच करने के पण्चात् 1 फरवरी, 1978 से दि रिजनल स्टेशन, केरल लाइव स्टाक डेवेनप-मेंट एण्ड मिल्क मार्केंटिंग बोर्ड लिमिटेंड, कुलाधुपुजा (केरल लाइव स्टाक डैवेलपमेंट एण्ड मिल्क मार्केंटिंग बोर्ड लिमिटेंड, रिजस्ट्रीकृत कार्यालय: 9/1148 सस्थामंगलम्, तिवेन्द्रम की इकाई) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्देष्ट करती है।

[सं॰ एस॰ 35019(81)/78-पी॰एफ॰ $\mathbf{H}(\mathbf{ii})$]

S.O. 1846.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of February, 1978 the establishment known as The Regional Station, Kerala Livestock Development and Milk Marketing Board Limited, Kulathupuzha (Unit of the Kerala Livestock Development and Milk Marketing Board Limited, Registered Office: 9/1148, Sasthamangalam, Trivandrum), for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(81)/78-PF-II(ii)]

कां आं 1847 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के जिं। अहमद कुट्टी एण्ड कम्पनी, पालीकान्वी मार्ग, कालीकट ग्राम, कालीकट सालुक, कालीकट जिला-3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियो की बहुस ब्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

म्रतः भ्रम, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह मधिसूचना 1 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं॰ एस॰ 35019 (82)/78-मी॰ एफ॰-II]

S.O. 1847.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis K. P. Ahammed Kutty and Company, Pallikandy Road, Calicut Village, Calicut Taluk, Calicut District-3 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1978.

[No. S. 35019(82)/78-PF-II]

कां आ 1848 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससँ लिघोटेक, 70/58,11 मुख्य मार्ग, इण्डस्ट्रियल टाउन, राजाजीनगर, ब्ंगलौर-44 नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और कर्मवारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मवारी भिष्ठिय निश्चि भीर प्रकीण उपबध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने वाहिए;

प्रतः प्रवः, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। [सख्याएस० 35019(83)/78 पी० एफ० II]

S.O. 1848.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees is relation to the establishment known as Messre Leotech, 70 58, II Main Road, Industrial Town, Rajajinagar, Bangalore-4-have agreed that the provisions of the Employees Provider Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force of the first day of March, 1978.

[No. S. 35019(85)/78-PF, II]

का० आ० 1849 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससं होटल एवरेस्ट, बिजीपुर, बेरहामपुर, जिला गंजम, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक भौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपबंध मिश्रिनियम, 1952 (1952 का 19) के उगबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

श्रतः श्रव, उक्त अक्षितियम की धारा । की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधित्यम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रकृत हुई समझी जाएमी।

[सं॰ एस॰ 35019 (85)/78 पी॰ एफ॰II]

S.O. 1849.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hotel Everest, Biznpur, Berhampur, District Ganjam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019(85)/78-PF, II]

का० आ० 1850 यतः केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत हांता है कि मैससं गुड़ शोफर्ड हास्पिटल सोसाइटी, वायपोरी साउथ वयनाउ, कोजीकोडे जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक श्रीर कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि श्रीर प्रकीण उपबंध श्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु किए जाने चाहिए;

श्रतः ग्रब, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रकत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त ग्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह प्रधिसूचना 31 मार्च, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं॰ एस॰ 35019 (86)/78-पी॰एफ॰-II]

s.o. 1850.—Whereas it appears to the Central Government at the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Good Shephered Hospital Society, Vythiri South Wyanad, Kozhikode District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1978.

[No. S. 35019(86)/78-PF-II]

का० आ० 1851 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसस गिक्त मैटल डिपो, बाजार भागें, कोचीन-2, मटनचेरी ग्राम, काचीन तालुक एर्नाकुलम जिला, जिसमें क्लाथ बाजार एर्नाकुलम कोचीन स्थित इसकी शाखा भी सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर प्रकीण उपयंध ग्रिक्षिनयम, 1952 (1952 का 19) के उनबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भतः प्रव, उक्त भिक्षितियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त भिक्षित्यम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1978 की प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं॰ एस॰ 35019(87)/78 पी॰एफ॰-H]

S.O. 1851.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sakti Metal Depot, Bazar Road, Cochin-2, Mattancherry Village, Cochin Taluk, Ernakulam, District including its branch at Cloth Bazar, Ernakulam, Cochin, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1978.

[No. S. 35019(87)/78-PF-U]

कां आं 1852 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे टाम्स बेकरी एण्ड स्टोर्स 1/2 व्हीलर रोड़, बंगलौर-5, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मकारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने वाहिए;

श्रतः श्रव, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह भ्रधिसूचना 1 मर्थ, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं॰ एस॰ 35019 (68) /78-पी॰ एफ॰II]

S.O. 1852.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thom's Bakery and Stores, 1/2, Wheeler Road, Bangalore-5, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1978.

[No. S. 35019(88)/78-PF-II]

कां आं 1853 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हैरी इलेक्ट्रानिक्स, जेल रोड़, कालीकट-2, केरल नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध प्रक्षिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

श्रतः भ्रव, उक्त भ्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदेस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त भ्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

यह प्रधिस्वना । प्रजैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं॰ एस॰ 35019(89)/78-पी॰ एफ॰ II)]

S.O 1853.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mcssrs Harry Electronics, Jail Road, Calicut-2, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Previsions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S. 35019(89)/78-PF-II]

कां आं 1854 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्सं स्पर प्राटो (इंग्डिया) प्रद्वेट निमिटेड, प्लॉट संख्या 62, सेक्टर-6, फरीदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक प्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी पत्रिय निधि ग्रीर प्रकोण उपवन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्ष स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भ्रतः श्रव, उक्त श्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1978 को प्रयुत्त हुई समझी जाएगी।

[स॰ एस॰ 35019(90)/78-पी॰एफ॰ $\mathbf{H}(\mathbf{i})$]

S.O. 1854.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Super Auto (India) Private Limited, Plot No. 62 Sector-6, Faridabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978,

[No. \$. 35019(90)/78-PF-1I(i)]

का० आ० 1855 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपजन्म ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रथस णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच करने के पण्चात् 1 मार्च, 1978 से मैसर्म सुपर आटो (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट सं० 62, सेक्टर-6 फरीदाबाद, नामक स्थापन को उन्नत परन्युक के प्रयोजनों के लिए थिनिर्दिश्ट करती है।

[स॰ एस॰ 35019 (90)/78 पी॰एफ॰ II)].

S.O. 1855.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1978 the establishment known as Messrs Super Auto (India) Private Limited, Plot No. 62, Sector-6, Faridabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(90)/78-PF. II (ii)]

का० आ० 1856 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर एलाय कास्ट, प्लाट सं० 62, सेक्टर-6, फरीदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक धौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि धौर प्रकीणं उपबध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

द्यतः श्रवः, उक्त श्रिधिनियम की धारा 1 की उनधारा (4) कारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त श्रिधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

S.O. 1856.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Super Alloy Cast Plot No. 2, Sector-6, Faridabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1978.

[No. S. 35019(91)/78-PF. II(i)]

का॰ आ॰ 1857 केन्द्रीय मरकार कर्मेचारी भविष्य निधि श्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध श्रीधनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध क्षय में शावायण जाँच करने के पश्चात् 1 मार्च, 1978 से मैसर्स

सुपर एलॉय कास्ट, प्लाट स॰ 62, सेक्टर-6, फरीवाबाव, नामक स्थापन कों उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के जिए विनिष्टि करती है।

[सं॰ एफ॰ 35019(91)/78-पी॰एफ॰ II(ii)]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

S.O. 1857.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of March, 1978 the establishment known as Messrs Super Alloy Cast, Plot No. 62, Sector 6, Faridabad for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(91)/78-PF, II (ii)]

S. S SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 13th June, 1978

S.O. 1858.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madrae in the industrial dispute between the employers in relation to the management of the Stevedores of Cochin Port and their workmen which was received by the Central Government on the 12th June, 1978.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B.A., B.L., INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Wednesday, the 24th day of May, 1978

Industrial Dispute No. 71 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Stevedores of Cochin Port, Cochin).

BETWEEN

The workmen, represented by:

- The Secretary, Cochin Dock Employees' Association, Door No. 2/100, Calvethy, Cochin-682001.
- The Secretary, Cochin Thuramugha Thozhilali Union, Mattancherry, Cochin-682002.
- Tile General Secretary, Cochin Port Thozhilali Union, INTUC Office, Mattancherry Cochin-682002.

And

- 1. M/s. Paul Abrao & Sons, Stevedores, Cochin-682003.
- M/s. South India Corporation (P) Ltd., Stevedores, Cochin-682003.
- 3. M/s. Achuthan Pillai & Co., Stevedores, Cochin-662003.
- 4. M/s. B. J. Khona, Stevedores, Cochin-682002.
- 5. M/s. O. P. Mummu, Stevedores, Cochin-682002.
- M/s. Poovath Parce & Sons, Stevedores, Cochin-682003.
- M/s. W. H. D. 'Cruz & Sons, Stevedores, Cochin-682003.
- 8. M/s, K. B. Jacob & Sons, Stevedores, Cochin-682001.
- M/s. New Tholera Shipping & Trading & Co., Stevedores Cochin-682002.
- 10. M/s C. V. A. Hydrose & Son, Stevedore, Cochin-682002.

1. M/s. United 'Stevedores' Association of Cochin (P) Ltd., River Road, Cochin-682001.

REFERENCE:

Order No. L-35011 (3)/77-D. IV (A), dated 2-12-1977 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 10th day of May, 1978 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other meterial papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal K. Damadora Gurup and K. A. Abraham, Advocates appearing for Union No. 1 and Thiru P. E. Thomas, Advocate for Union No. 2 and of Thiru P. Kurian for Menon and Pai, Advocates for the Managements and Union No. 3 being absent and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This is a reference by the Government of India under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of an Industrial Dispute between the Management of Stevedores of Cochin Port and photo pass casual workers in the matter of wages as recommended by the Wage Revision Committee.

(2) The reference is as follows:

Whether the stevedores of Cochin Port are justified in not granting to the photo pass casual workers the arrears from 1-1-1974 to 31-3-1975 in terms of new wage rates recommended by the Wage Revision Committee as accepted by the Government of India in Resolution No. LWR-20/77-D. If dated the 17th August, 1977 of the Ministry of Shipping and Transport? If not, to what relief are these workmen entitled?

(3) Union No. 1 filed a claim statement, wherein they state as follows: The photo pass casual workers are engaged by the Stevedores Association for the purpose of loading and unloading and discharge of cargo in the Cochin Port. They are employed through the Cochin Dock Labour Board along with the registered workers ever since 1962. When the Dock Workers Regulation of Employment Scheme was implemented in 1962, it was decided on the basis of trade needs that only 1832 workers need be registered out of the total 3000 workers for regular engagement under the Dock Labour Board. The remaining workers were continued as temporary workers to meet the overflow requirements in the mater of cargo handling. Subsequently in 1972 a seniority list of those non-registered and not decasualised temporary workers were prepared and the total number thus fixed was 365. Though these workers were in service continuously for 15 years, they have not been decasualised though the workload has increased and a number of registered workers retired. The present strength of registered workers is only 750. They are quite inadequate to meet the requirements of the Port. The inadequacy was made good by the photo pass casual workers for the past several years. So far as the wage is concerned, there is no difference. But there is distinction regarding their attendance money, minimum guarantee etc. The Government of India by its resolution dated 17-8-1977 Clause 5, decided to accept the recommendations of the Wage Revision Committee and the Wage Revision Committee recommended in its report for mayment of revised pay scale with effect from 1-1-1974. Under the Recommendation, all the sections of the em-Port were paid their arrears of pay effective from 1-1-1974. Similarly in other Ports also the recommendations were given effect to. But the Management in Cochin Dock Labour Board alone refused to pay the arrears of these workers from 1-1-1974 but restricted the same from 1-4-1975. The workers and the Unior protested against this action as it is against the recommendation and the spirit of the agreement made with the federation. The dispute was raised in the Dock Labour Board. Due to unreasonable attitude of the Management in the Cochin Dock Labour Board, a memorandum of demands consisting of decasualisation of listed workers and of pay from 1-1-1974 was submitted before Labour Officer a strike notice on 14-10-1977 was issued by the Union. The conciliation failed. Hence the matter was referred for adudication to this Tribunal.

- (4) Union No. 2 also filed a claim statement on the same lines as the claim statement of Union No. 1.
 - (5) Union No. 3 has not filed claim statement.
- (6) The Management filed a counter, wherein they contend as follows: There was an award on the basis of a compromise between the labour and the Management in the matter of registration of casual workmen on employing as stevedore labour. As per the Award 1832 casual workmen in the categories of tindals, which drivers, signallers and mazdoors were decasualised and registered in reserve pool. The compromise award provided that casual workmen should be provided with work when the registered workers were not available. It was also made clear that they were not entitled to the benefit which available to the registered workers. As per the Award, a provisional list of casual workers was prepared in 1966 and the strength was fixed at 637. The Board decided to issue photo-passes to all the workers included in the provisional list. The conditions at the Cochin Port considerably and as a result, the appointment of dock workers got considerably reduced. As on 1-1-1978, the number of workmen in the various categories, were only 747 registered workers. The other categories on the said date is 234. In place of 637 workmen included in the provisional list of photo-pass holders, the number excluding tally clerks, as on the same date is 376 and there are 18 photo-pass casual tally clerks. There is not enough work even at the present strength. From the period 1-1-1969 until 31-3-1975, the photo-pass casual workers were paid Rs. 8.30 per day. From 1-4-1975, they were placed in the bottom of the scale applicable to mazdoors with no right for increments being casual workers. In addition to the basic pay in the lowest step in the scale, they were given dearness allowance, house-rent allowance, city compensatory allowance and additional dearness allowance at the same rate applicable to the mazdoors in he reserve pool. The interim relief as recommended by the Wag. Revision Committee was extended to the photopass casual workers from 1-4-1975. In terms of the agreement entered into between the Government of India and the representatives of the workmen and as clarified by the Government of India, the retrospective operation of the recommendations of the Wage Revision Committee as accepted by the Government of India was to be given only from 1-4-1975 bring the date from which interim relief was given. Therefore, they are not entitled to payment from 1-1-1974.
- (7) ISSUE: The point to be considered is whether the photo-pass casual workers are entitled to new wages from 1-1-1974 to 31-3-1975.
- (8) It is admitted by the Management that the recommendations of the Wage Revision Committee were accepted by the Government of India and were given effect to and the wages in respect of photo-pass casual workers were revised on the basis of the recommendations from 1-4-1975 It is also the admitted case that revised scales had come into force from 1-1-1974 and the recommendations of the Wage Revision Committee were implemented in respect of other categories from 1-1-1974 except this categories f workers, viz., photo-pass casual workers. It is to be noted that these photo-pass casual workers entitled to all benefits just like other categories of workers. But there is discrimination only in respect of photo-pass casual workers ever the denial of the revision of waces for the period from 1-1-1974 to 31-3-1975. When the Management had chosen to deny them the revised scales of pay and other benefits as per the recommendations Wage Revision Committee, it is the duty of the Management to state reasons for denying the increase in the wages and conferring other benefits. On perusal of the counter, I am not able to see any reason for denying them of the benefit of the wage revision excepting the fact that the photo-pass casual workers were given interim relief from 1-4-1975 onwards only. I am of view that it is not a ground to reject their just demand. The reasoning of the Management is that these categories of persons were not enjoying interim benefit like other categories prior

to 1-4-1975. Such a ground is untenable, for, we find that the time rate of Rs. 8.30 was fixed in 1970 taking into account Basic pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance and City Compensatory Allowance, as recommended by Central Wage Board and they were enjoying the wages and other emolumens on par with the registered workers and they were also beneficiaries of the recommendations of the Wage Revision Committee like other categories of workers. The Management's contention is that it was only an ad hoc fixation. I do not agree with such a contention. Ex. M-5 is a Settlement arrived at between the Government of India and the Federations of Port and Dock workers on the implementation of the 1 cport of the Wage Revision Committee. Ex. M-5 would clearly show that the recommendations of the Wage Revision Committee came into effect from 1-1-1974. Ex. M-1 is a letter from the Ministry of Shipping and Transport, Government of India to all Port Trusts and All Dock Labour Boards. This was relied upon by the Management that the interim relief was effective only from 26-2-1975. 26-2-1975 is the date of Ex. M-1. Ex. M-4 is the telex message regarding payment of interim relief to casual workers who are neither registered nor listed with the Dock Labour Board and the benefit of interim relief is admissible only to those who are covered by the term "Employee". It contains also the reply by the Deputy Chairman for clarification. Ex. M-3 is a letter by the Deputy Chairman for clarification. Ex. M-3 is a letter by the Deputy Chairman to the Under Secretary to Government of India, Ministry of Shipping and Transport relating to the payment of additional Dearness Allowance to casual workers. Ex. M-2 is the reply to Ex. M-3 stating that they have no objection to the payment of interim relief to the casual workers of the Dock Labour Board with effect from 1-4-1975. On the above correspondence relied upon by the Management they were entitled to the benefit of the recommendations of the Wage Revision Committee only for the period fr

"In the case of casual workmen whether the benefit of Wage Revision is to be given or not may be decided with reference to the fact whether these casual workmen are getting interim relief or not".

But the above communication has no significance and this Tribunal has to go into the spirit of the recommendations of the Wage Revision Committee. Clause (vii) Appendix XXIX of the Book 'Report of the Wage Revision Committee for Port and Dock Workers at Major Ports' runs as follows:

"Similar categories of employees as covered under clause (v) ["Employees covered by the Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes at the ports of Bombay, Calcutta, Madras and Kandla"] above at the port of Cochin, Visakhapatnam, Mormugao and Paradeem".

Having regard to the above provision it is clear that photopass casual workers in Cochin Port are equated to the Registered dock workers and as such they are entitled to pay revision from the date of 1-1-1974 like others. Therefore, there is no substance in the contention of the Management that they will be entitled to the revised scale of pay from the period of 1-4-1975, the date of interim relief in the face of the specific mention in report of the Wage Revision Committee. Therefore, my finding on this point is that the photo-pass casual workers will be entitled to the benefit of wage rates recommended by the Government from 1-1-1974 and as such they will be entitled to the arrears for the period from 1-1-1974 to 31-3-1975.

9. An Award is passed accordingly. Dated, this 24th day of May, 1978.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For both sides: Nil

DOCUMENTS MARKED

For workmen

Ex. W-1/6-9-77—Certified copy of record of discussions regarding payment of wage revision arrears to photopass casual workers.

For Management

- Ex. M-1/26-2-75—Letter from the Ministry of Shipping and Transport, Government of India to all Port Trusts and All Dock Labour Boards regarding payment of interim relief to Port and Dock Workers (True copy).
- Ex. M-2/23-7-75—Letter from the Ministry of Shipping and Transport, Government of India to the Cochin Dock Labour Board regarding payment of interim relief to casual workers (True copy).
- Ex. M-3/14-7.75—I etter from the Cochin Dock Labour Board to the Ministry of Shipping and Transport, Government of India regarding payment of interim relief to casual workers (True copy).
- Ex. M-4—Telex message from the Ministry of Shipping and Transport, Government of India to the Cochin Dock Labour Board and another from the Cochin Dock Labour Board to the Central Government regarding payment of interim relief to casual workers (copy).
- Ex. M-5/14-7-77—Settlement between the Government of India and the Federations of Port and Dock Workers on the implementation of the report of Wage Revision Committee (copy).
- Ex. M-6/4-8-77—D. O. letter from the Director of Ministry of Shipping and Transport, New Delhi to the Chairman Cochin Port Trust (True copy).
- Ex. M-7/17-8-77.—Resolution of the Government of India relating to implementation of Wage Revision Committee recommendations.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer
[No. L-35011(3)/77-D. IV(A)]

S.O. 1859.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cochin Port Trust, Cochin-682003 and their workmen which was received by the Central Government on the 12th June, 1978.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B. A., B. L., INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Tuesday, the 23rd day of May, 1978 Industrial Dispute No. 70 of 1977

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Cochin Port Trust, Cochin).

BETWEEN

The workmen, represented by

The General Secretary, Cochin Port Wharf Staff Association, Cochin-682003.

AND

The Chairman, Cochin Port Trust, Cochin-682003. REFERENCE:

Order No. L-35011(4)/77-D.IV(A); dated 2-12-1977 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 10th day of May, 1978 upon perusing the reference, claim and counter-statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. Balagangadhara Menon, Advocate appearing for the workmen and of Thiru P. K. Kurian for Menon and Pai, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribural made the following.

AWARD

This is a reference by the Government of India under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of an industrial dispute between the Management of Cochin Port Trust, Cochin and their Outdoor Wharf Staff of Cochin Port Trust over the payment of additional amount at 10 per cent of the revised basic pay as recommended by the Wage Revision Committee.

2. The reference is as follows:

Whether the demand of the Outdoor Whatf-Staff of Cochin Port Trust for payment of additional amount at 10% of the revised basic pay in the revised pay scale recommended by Wage Revision Committee as accepted by the Government of India, Ministry of Shipping & Transport, in their Resolution No. LWR-20/77-D. If dated 17-8-77 with retrospective effect from 1-1-1974 is justified? If so, to what relief are the employees concerned entitled?

3. The Union filed a claim statement, wherein they state as follows: The Cochin Port Wharf Staff Association is a Trade Union registered under the Indian Trade Unions Act with its registered office at Cochin-3 in Ernakulam District in the State of Kerala. The membership of this Staff Association consists of all Class III and Class IV employees of the Wharf Establishment of the Cochin Port, The total number of Employees employed in Class III and Class IV is about 563, of which 463 persons are members of the Cochin Port Wharf Staff Association. The staff employed on clerical work in the Cochin Port can be broadly classified into employees doing clerical and supervisory staff in the offices and those working outdoor. The clerical staff working in administrative offices and other main offices are classified as indoor clerical staff and other main offices are classified as indoor clerical staff and their working hours are 6-1/2 hours per day and 36 hours per week. The working hours are from Monday to Friday 10.00 A.M. to 5.00 P.M. with half an hour interval and on Saturdays from 10.00 A. M. to 1.30 P. M. The clerical staff working outside the administrative and Main offices have been classified as outdoor clerical staff. The Wharf Staff "Class III" belongs to the outdoor clerical category. Their "Class III" belongs to the outdoor clerical category. Their working hours are 8 hours in a day or 48 hours in a week. Thus they worked 3 hours per day and 12 hours a week more than the indoor clerical staff. The Wharf Staff made a claim than the indoor clerical staff. for a reduction of duty hours so as to bring it to the same level as indoor clerical staff. But the Port Authorities did not agree to reduction of working hours and constituted a sub committee of the Board of Trustees of Cochin Port by resolution of the Board dated 23-11-1972. The sub committee after taking into consideration the representations of the affected parties and after examining the nature of duties of the outdoor clerical staff unanimously decided to recommend to the Board the payment of an additional amount of 10 per cent of the basic pay of the Wharl Staff as compensation for the extra hours of work until an alternative arrangement is made. The recommendations of the sub committee came up for consideration before the Board of Trustees and the Board resolved on 24-2-1973 to accept the recommendations without any alteration. Thus the Wharf Staff are getting 10 per cent of their basic pay as compensation for the extra bours of work from basic pay as compensation for the extra hours of work from 24-2-1973 The Government of India by their proceedings dated 11-12-1974 set up a Wage Revision Committee to make enquiries and make recommendation in the matter of existing wage structure of the employees. The Committee found that the demand of the outdoor workers were justified. They are also found that there should not be any discrimination in the working hours and both categories of staff should work for 8 hours a day. But they did not recommend outdoor allowance from the date of Government decision on the wage revision committee report from 17-8-1977. The recommendation of the Committee was the subject matter of the decision with the representatives of the four all India Federations of the Port 266 GI/78—6

and Dock Workers in June and July, 1977. As a result, a memorandum of settlement was signed between the Government and the Federations on the 14th of July, 1977 for the implementation of the recommendations of the Wage Revision Committee with effect from 1-1-1974. As a result of the Settlement and the decision of the Government the outdoor workers are not to be deprived of an additional amount of 10 per cent of the basic pay as compensation for extra hours of work. By the proceedings dated 17th August, 1977, the Government of India implemented the new scales of pay from 1st January, 1974 and the Wharf Staff are entitled to be paid compensation for extra hours of work at 10% of the revised basic pay as before. But to their surprise, the Cochin Port Trust contrary to the decision of the Government to implement the decision of the Wage revision unilaterally decided on 13th of August, 1977 that the outdoor allowance will be payable at 10 per cent of the maximum of the pre-revised scale for each category and thereafter a circular was issued by the Cochin Port Trust dated 25th August, 1977 directing payment of 10 per cent of the maximum of the pre-revised scale as compensation. Thus the decision of the Port Trust is illegal and they protested against the decision of the Port Trust and did not agree and the direct negotiations also failed. Hence the matter was referred to the Tribunal. Hence the Tribunal may be pleased to fix the compensation for doing extra hours of work calculating it at 10 per cent of the revised basic pay with effect from 1-1-1974.

4. A counter-9-atement was filed by the Management denying all the allegations contained in the claim petition. They state as follows: In 1972, the Wharf Staff made a demand for reduction in the working hours so as to bring it in level with that of the indoor clerical staff, the Board of Trustees of the Cochin Port Trust constituted a sub-committee by Resolution dated 23-1-72, to go into the matter. The Sub-Committee made an Interim recommendation recommending the payment of additional amount at 10 per cent of the basic pay of the wharf staff as compensation for the extra hours of work until such time as the Board is in a position to make an alternative arrangement or a decision on an a'l-India level is arrived at when the recommended benefit of compensation will be discontinued. Following the recommendation, the Board in its meeting on 24-2-1975, accepted the recommendations of the Sub-Committee. On the basis of this interim arrangement, the Wharf Staff who worked for the normal 8 hours a day were given an extra payment at 10 per cent of their basic pay. A Wage Revision Committee was set up by the Government of India in 1974 in respect of employees in the major ports in India. The Wage Revision Committee recommended that there was no justification for reduction in the working hours of outdoor staff nor is there any justification for payment of overtime and such practice should be discontinued and it should come into effect prospectively. In view of the recommendation the practice was discontinued with effect from the date of Government accepting the recommendations of the Wage Revision Committee. In the settlement between the Government of India and the Federations of Port and Dock Workers on the implementation of the Report of the Wage Revision Committee on 14-7-1977 by Clause (m), it was provided that any facility prevailed and enjoyed by the workers should not be reduced by reason of the recommendations of the Wage Revision Committee and it can be reduced or withdrawn to the extent and manner as provided for in the agreement. In the face of the above terms of Settlement, what was paid for the extra hours of work could be construed at best only as a benefit. Viewed in that light, they would be entitled to payment of 10 per cent of the then basic pay prior to the implementation of the re-commendations of the Wage Revision Committee and they cannot claim payment of 10 per cent on the basis of the revised basic scales by the Wage Revision Committee.

- 5. ISSUE: The point that arise for consideration is whether the Wharf Staff are entitled to 10 per cent of the revised basic pay by the Wage Revision Committee from 1-1-1974.
- 6. The contention of the Management is that 8 hours work a day is a normal rule and it should be applied both to the Indoor Staff of the Port as well as the Outdoor Staff viz., the workers in the Wharf. They cannot claim extra benefit which they were enjoying by way of interim arrangement before the recommendations of the Wage Revision Committee and after the Government accepted the principle that 8 hours a

day is a normal rule and there was no justification for the Wharf staff to claim the extra benefit. Their further contention is, assuming that they are entitled to extra benefit, at best they will be entitled to 10 per cent on the basis of the pay prior to the revision of scales of pay as recommended by the Wage Revision Committee and accepted by the Government in 1977. I have to consider what was the spirit of the recommendations of the Wage Revision Committee. Fx. M-1 is the extract of the Wage Revision Committee Recommendations. The relevant passages are Paragraphs 8.76, 8.77 and 8.80. In paragraphs 8.80, it is stated as follows:

1708

"We have given careful thought to the issue, Prima facie, the present discrimination in working hours in favour of indoor ministerial employees working in relatively more comfortable surroundings is not equitable. While it may be possible, as in Visakhapatnam Port, to reduce the working hours of some categories of outdoor ministerial staff, it may not be feasible for operational reasons to reduce the working hours of those categories of outdoor ministerial staff who have to work throughout the shift alongside the outdoor operational staff. staff. Apart from that, the outdoor ministerial staff is recruited with the tacit understanding that their working hours would be 8 a day or 48 a week. There is, therefore, no justification for reducing the working hours of those who are employed with such understanding or for paying them for supposed extra hours of work. In our view, port organisations being industry-oriented, the normal rule should be 8 hours duty for both indoor and outdoor staff." outdoor staff"

It is clear from the above said observation that there cannot be a distinction between the working hours between the indoor workers and the whatf staff. All should work 8 hours a day. The basis of the Union's claim is that the payment which they were entitled should be construed as a benefit and they should not be taken away by reason of the recommendations of the Wage Revision Committee and that was recognised by the Settlement Ex. M-2 dated 14-7-1977. Clause (m) of Ex. M-2 is provided as follows:

"Merely as a consequence of implementation of the recommendations of the W.R.C. any facility, privilege, amenity, benefit monetary or otherwise, or concession to which an employee might be entitled by way of practice or usage shall not be withdrawn, reduced or curtailed except to the extent and manner as provided for in this Agree. extent and manner as provided for in this Agreement".

It is admitted by reason of such Settlement, the Port Trust, while implementing the recommendations of the Wage Revision Committee, directed payment of allowance at 10 per cent of the maximum of the pre-revised scales applicable to each category of employees from the date of the Government's resolution. But the Union is not satisfied, and what they want is, they should be paid 10 per cent as the revised basic pay in the new scales. In view of the the revised basic pay in the new scales. In view of the Wage Revision Committee Recommendations as accepted by the Government, the Wharf Staff as well as the indoor staff should do 8 hours a day. If the Wharf staff ket 10 per cent of the basic pay it can be construed only as a benefit conferred on the wharf staff Now the Union wants the cytra benefit which they arised the late. the extra benefit which they enjoyed should be linked with the enhanced pay revision as recommended by the Wage Revision Committee and accepted by the Government. It is significant to note that Wage Revision Committee was quite silent about it. When there is no such provision in the Wage Revision Committee Recommendations, the Tribunal has to construe it strictly. Clause (m) of the Settlement Ex. M-2, which provides that there should not be any reduction or curtailment in the remetary benefit. When once the principle of 8 hour, work is acceptant the extra payment of 10 per cent at the old rate of pur should be construed. Now the Union wants inly a a moneture benefit to enhance the benefit of the reside, scales of pay which I feel it is not justified beginning record to the Ex. M-2, which provides that there pay, which I feel it is not justified having regard to the spirit of the Agreement arrived at under Ex. M-2. Therefore my answer on this point is that there is no justifica-tion for the demand by the Union for the payment of additional amount at the rate of 10 per cent on the revised basic pay in the revised wage scales as recommended by the Wage Revision Committee.

7. In the result, an demand of the workers. Award is passed negativing the

Dated, this 23rd day of May, 1978.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer.

WITNESSES EXAMINED

For both sides: Nil.

DOCUMENTS MARKED

For workmen:

- Ex. W-1—Recommendations of the Surgarding deduction of working hours. Sub-Committee
- Ex. W-2/27-4-77—Memorandum of the Indian National Port and Dock Workers Federation to the Government of India in respect of Wage Revision Committee Recommendations (copy).
- Ex. W-3/24-8-77—Letter from the Union to Management preferring payment of 10 per extra wages (copy),
- Ex. W-4/13-10-77—Letter from the Union to the Management requesting to settle the demands
- Ex. W-5-Reply letter from the Management to Ex. W-4 (copy).
- Ex. W-6-Resolution of the Board of Trustees of the Cochin Port Trust (copy).

For Management:

- Ex. M-1—True extract of paragraphs 8.76 to 8.82 from the Wage Revision Committee Recommendations relating to payment for outdoor work.
- Ex. M-2/14-7-77—Settlement between the Government of India and Federations of Port and Dock Workers on the implementation of Wage Revision Committee Report (copy).
- Ex. M-3/30-7-77—Clarificatory Telex Message from the Ministry of Shipping and Transport to the Cochir Port Trust regarding payment of 10 per cent outdoor allowance (copy).

K. SELVARATNAM, Presiding Officer

[No. I.-35011(4)/77-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer.

